सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 16 अंक - 356 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 08 अक्टूबर 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

रायपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान, बेटिकट पकड़ाए 263 यात्री

रायपुर। यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से 07 अक्टूबर, 2025 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में सहायक वाणिज्य प्रबंधक (गुड्स) शेष मणि पांडे एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) अविनाश कुमार आनंद के साथ में 05 वाणिज्य निरीक्षक, टिकट चेकिंग स्टाफ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय के 45 स्टाफ शामिल हुए साथ ही 09 रेलवे सुरक्षा बल के जवान शामिल थे।

यह किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान रायपुर स्टेशन पर सुबह 6:00 से रात्रि के 10:00 तक चलाया गया। सुबह 6.00 बजे से रात 8 बजे तक कुल 263 मामलों से 95630 रुपए बतौर जुर्माना राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें बिना टिकट के 202 मामलों से 80815 रुपए एवं अनियमित टिकट के 34 मामलों से 11715 /-रुपए अनबुक्ड लगेज के 21मामलों से 2200/- रुपए धूम्रपान के तीन मामलों से ?600, कचरा फैलाने वाले तीन मामलों से ?300 राजस्व प्राप्त हुआ। रेल प्रशासन यात्रियों से आग्रह करता है कि वे यात्रा हेतु उचित टिकट एवं रेल परिसर में प्रवेश करने के पहले प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य खरीदें। रेलगाड़ी एवं रेल परिसर को साफसुथरा रखने में भी रेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

नक्सली कमांडर मंडा रूबेन ने किया तेलंगाना में सरेंडर

जगदलपुर। नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे अभियान के चलते नक्सली संगठन कमजोर होते जा रहे हैं, एक-एक कर नक्सलियों की टीम कमजोर होकर अपने दल का साथ छोड़कर पुलिस की खुली विचारधारा में जुड़कर अपने लिए आगे के मार्ग को खोल रही है। इसी अभियान को देखते हुए दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य मंडा रूबेन ने तेलंगाना में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते नक्सलियों की टीम और भी कमजोर हो गई है, बताया जा रहा है कि इसी नक्सली ने कई वर्ष पहले दंतेवाड़ा की जेल में अपने चार साथियों के साथ मिलकर भाग निकलने में सफल भी हुआ था।

तेलंगाना पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर के एक और बड़े नक्सली कमांडर मंडा रूबेन उर्फ सुरेश ने तेलंगाना में आकर सरेंडर करते हुए लाल गलियारे से अपने आप को अलग कर लिया है। नक्सली कमांडर मंडा रूबेन नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य होने के साथ ही नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेंटी का सचिव भी था, 67 साल का रूबेन बीते 44 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। अन्य नक्सलियों के द्वारा किये जा रहे सरेंडर को देखते हुए अपना मन बनाने के बाद छत्तीसगढ़ की जगह तेलंगाना में सरेंडर किया है।

कोड़पाली एवं लारा जलाशय के लिए 3.26 करोड़ रुपए की स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-पुसौर के अंतर्गत कोड़पाली एवं लारा जलाशय के जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 3 करोड़ 26 लाख 79 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। जलाशय योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण हो जाने पर योजना का रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 114 हेक्टेयर में 114 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के कार्यों को पूरा कराने के लिए जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

लोगों को मिले जीएसटी की घटी दरों का लाभ

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की 'जीएसटी बचत उत्सव' की विशेष समीक्षा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नवा रायपुर में आयोजित 'जीएसटी बचत उत्सव' की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के नागरिकों को जीएसटी की घटी दरों का त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए, ताकि हर परिवार को वास्तविक बचत और व्यापारियों को राहत मिल सके।

वित्त मंत्री चौधरी ने बैठक में राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जीएसटी दरों में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पारदर्शी रूप से पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दरों में ऐतिहासिक कमी की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और व्यापार को सुगमता प्रदान करना है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस सुधार का लाभ समयबद्ध और ईमानदारीपूर्वक जनता तक पहुंचे।

99 फीसदी वस्तुओं पर लग रही 5 प्रतिशत जीएसटी

गौरतलब है कि आम उपयोग की वस्तुओं की दरों में व्यापक कमी की गई है। लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाई गई हैं। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बड़ी बचत हो रही है। उदाहरण के तौर पर, ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी पर 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपए तक की बचत संभव हुई है। वहीं, कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे आमजन का वार्षिक खर्च काफी घटेगा।

पुराने स्टॉक पर रखी जाए निगरानी

वित्त मंत्री चौधरी ने सभी जिलों के जीएसटी अधिकारियों से कहा की वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वस्तु पुरानी दरों पर न बेची जाए। यदि कोई पुराना स्टॉक उपलब्ध हो, तो उस पर नई संशोधित दरें अंकित की जाएँ और वस्तुएँ केवल नई दरों पर ही बेची जाएँ, ताकि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचे। उन्होंने यह भी कहा कि 'जीएसटी बचत उत्सव' की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी और राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा वे स्वयं करेंगे, ताकि जीएसटी 2.0 सुधारों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके। यह बैठक वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी, वित्त सचिव मुकेश बंसल तथा आयुक्त, राज्य कर पुष्पेन्द्र मीणा की उपस्थिति में आयोजित की गई।

जीएसटी 2.0 सुधारों से आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ

22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी 2.0 सुधारों का उद्देश्य आम भारतीय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। इन सुधारों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अब जीएसटी मुक्त हैं, जिससे परिवारों को सालाना हजारों रुपये की बचत होगी. अधिकांश दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी दर 12 फीसदी से 5 फीसदी कर दी गई है, जबकि कई जीवनरक्षक दवाइयां पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दी गई हैं। इन सुधारों से न केवल आम नागरिकों को स्वास्थ्य खर्च में राहत मिली है, बल्कि घरेलू बजट पर सकारात्मक असर भी पड़ा है।

131 फीट ऊंचाई से गिरी लिफ्ट, 3 मजदूरों की मौत

■ सक्ती के आरकेएम पावर प्लांट में बॉयलर मेंटेनेंस के दौरान हादसा, 7 मजदूरों की हालत गंभीर

श्रीकंचनपथ न्यूज

सक्ती। छत्तीसगढ़ में सक्ती जिले के डभरा स्थित आरकेएम पावर प्लांट में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मेंटेनेंस के दौरान मजदूरों को ले जा रही एक लिफ्ट करीब 40 मीटर की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर गई। इस घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार 10 मजदूर लिफ्ट में सवार होकर पांचवी मंजिल तक जा रहे थे। जिसकी ऊंचाई करीब 75 मीटर है, लेकिन 40 मीटर तक पहुंचने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। इस घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मामला डभरा थाना क्षेत्र का है। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सभी घायल मजदूरों को निजी फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सक्ती एडिशनल एसपी हरीश यादव ने बताया कि लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हैं। सभी मजदूर बॉयलर की मरम्मत के कार्य में लगे थे। हादसे के बाद प्लांट में काम कर रहे मजदूरों में आक्रोश फैल गया। स्थिति को देखते हुए डभरा पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। फ्लिहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस मौके पर मौजूद है।

मजदूर बोले- प्रबंधन की लापरवाही से हादसा हुआ

स्थानीय मजदूरों ने आरोप लगाया है कि पॉवर प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट की नियमित तकनीकी जांच लंबे समय से नहीं की गई थी। घटना के बाद प्लांट प्रबंधन के खिलाफ मजदूर में आक्रोश है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

मृतक के परिजन और मजदूरों ने किया हंगामा

हादसे के बाद मजदूरों के परिजन और अन्य मजदूर प्लांट गेट के बाहर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही डभरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। हालांकि, प्लांट प्रबंधन और सुरक्षा विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं।

कफ सिरप से तीन और मासूमों की मौत एमपी में अब तक 20 बच्चों की गई जान

■ 'कोल्ड्रिफ' के मालिक को गिरफ्तार करेगी पुलिस

छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में तीन और मासूमों ने दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 20 पर पहुंच गई है। छिंदवाड़ा में 17, पांढुर्ना में एक और बैतूल में दो बच्चों की मौत हो चुकी है। पांच बच्चे अब भी नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अब कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के ऑनर को गिरफ्तार किया जाएगा। उसे पकड़ने के लिए दो टीम चेन्नई और काछीपुरम पहुंच चुकी हैं।

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और बैतूल को मिलाकर अब तक 20 बच्चों की जान जा चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। आरोपी कंपनी, कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के ऑनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा पुलिस की टीम चेन्नई और काछीपुरम पहुंच चुकी है। आईएनएस के हड़ताल पर जाने पर शुक्ल ने कहा कि वो हड़ताल पर न जाएं, अपना काम करें। चार साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरफन देने की जो भारत सरकार, आईसीएमआरसी की एडवायजरी है, उसका पालन करने का निवेदन किया है। शुक्ल ने कहा कि मैं कल नागपुर में गया था। वहां पांच बच्चे भर्ती हैं। वहां परिजनों से मिला और बच्चों की देखा। सभी लोग बच्चों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की बेटी, देश का गौरव : लखनी साहू को मिला MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की माटी ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कोरबा जिले की लखनी साहू, ई. विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज की एनएसएस स्वयंसेविका ने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23) से सम्मानित किया है। यह उपलब्धि न केवल लखनी साहू के अथक प्रयासों की पहचान है, बल्कि हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मान पर लखनी साहू को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाजहित में किए गए उनके योगदान ने यह सिद्ध किया है कि जब युवा संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, तो परिवर्तन निश्चित होता है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को देश सेवा और जनकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देकर उन्हें समाज निर्माण और राज्य के नवोदय में सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ में औसत से ज्यादा बारिश, बलरामपुर में सबसे ज्यादा और बेमेतरा में सबसे कम बारिश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब तक 1196.2 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 1619.1 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 548.7 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।

रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1135.8 मिमी, बलौदाबाजार में 990.9 मिमी, गरियाबंद में 1213.4 मिमी, महासमुंद में 1038.5 मिमी और धमतरी में 1138.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में

बिलासपुर जिले में 1194.8 मिमी, मुंगेली में 1170.9 मिमी, रायगढ़ में 1386.8 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1103.9 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1398.1 मिमी, सक्ती में 1270.0 मिमी, कोरबा में 1174.9 मिमी और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1103.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 935.6 मिमी, कबीरधाम में 866.0 मिमी, राजनांदगांव में 1004.9 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1458.2 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 893.8 मिमी और बालोद में 1289.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 792.4 मिमी, सूरजपुर में 1174.0 मिमी, बलरामपुर में 1578.4 मिमी, जशपुर में 1089.7 मिमी, कोरिया में 1244.6 मिमी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1132.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1599.3 मिमी, कोंडागांव जिले में 1188.5 मिमी, कांकेर में 1394.1 मिमी, नारायणपुर में 1456.0 मिमी, सुकमा जिले में 1275.0 मिमी और बीजापुर जिले में 1613.0 मिमी की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

मछली को बचाने युद्धपोत तैनात

श्रीकंचनपथ

एक विलक्षण घटना के तहत बांग्लादेश ने 'हिल्सा' मछली को बचाने के लिए युद्धपोतों को तैनात किया है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर द्वारा 'हिल्सा' प्रजनन क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। यह तैयारी ही यह बताने के लिए काफी है कि जिसकी सुरक्षा के लिए ये इंतजाम किये गये हैं, वह मछलियों की महारानी है। दरअसल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और दुनिया भर में रहने वाले बंगालियों के बीच 'हिल्सा' बहुत पसंद की जाती है। बंगाली भाषा में इसे ईलीश कहा जाता है। पद्मा नदी में पाई जाने वाली हिल्सा की मांग सबसे ज्यादा है। यह मछली नदी और समंदर दोनों के बीच आना जाना करती है। आम तौर पर समुद्र के खारे और ऊष्ण जल में रहने वाली हिल्सा प्रजनन के लिए शांत नदी की ओर लौटती है। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच के समय को इसका प्रजनन काल माना जाता है। इस दौरान इन मछलियों का शिकार प्रतिबंधित रहता है पर चोरी छिपे यह चलता रहता है। इसकी वजह से इसका प्रजनन बाधित होता है जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है। इस बार सरकार ने 17 युद्धपोतों को इसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया है। इनके साथ आकाश से इस इलाके की निगरानी हेलीकॉप्टर द्वारा की जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पानी में युद्धपोतों की उपस्थिति इस मछली के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं क्योंकि ये शांत शीतल जल पसंद करती है। बेहतर होता कि मछली चोरों और तस्करों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता। इस मछली के वीवीआईपी होने की वजहों पर आते हैं। नदी में रहने के बावजूद इसमें समुद्री मछली जैसा स्वाद होता है। बांग्लादेश में इसकी कीमत 2800 से 3000 टका प्रति किलो है। भारत में इसकी कीमत उपलब्धता के अनुसार इससे भी अधिक हो सकती है। पर मामला सिर्फ वाणिज्यिक नहीं है। बांग्लादेश हिल्सा का प्रमुख निर्यातक है, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है। कुल मछली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है। बांग्लादेश के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 3-4 फीसदी है। पर यह इसकी इकलौती पहचान नहीं है। बांग्लादेश के लिए हिल्सा मछली अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चाभी भी है। हसीना सरकार के गिरने के बाद सत्ता में आई यूनूस सरकार ने भारत को हिल्सा का निर्यात रोक दिया। हालांकि सितम्बर में इसे दोबारा शुरू कर दिया गया। इसे 'हिल्सा डिप्लोमैसी' कहा गया। बांग्लादेश के पास हिल्सा का जीआई टैग भी है। स्पष्ट है कि बांग्लादेश अपने यहां पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा को लेकर हमसे कहीं ज्यादा सतर्क है। यूनूस को महिला स्वसहायता समूह के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। हिल्सा की सुरक्षा का प्रयास प्रथमदृष्टया हास्यास्पद लग सकता है किन्तु गहराई में जाएं तो यह मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित रखने के साथ अपनी पहचान को कायम रखने की कोशिश भी है। लगभग 5 लाख मछुआरे और इससे जुड़े उद्योगों में 20 लाख लोगों को आजीविका मिलती है।

संपादकीय

आत्मनिर्भरता की आत्मघाती बाधा, खाद्य पदार्थों के साथ दवाओं की गुणवत्ता भी सही नहीं

हैरानी नहीं कि बहुत कम भारतीय उत्पाद ऐसे हैं जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चूंकि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय नहीं बन पा रहे हैं इसलिए वे विश्व बाजार में अपनी छाप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी कारण हम आत्मनिर्भर बनने के अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों विषाक्त कफ सीरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत का मामला चर्चा में है। हर तरफ आक्रोश है और उसके चलते जांच एवं कार्रवाई की बातें हो रही हैं। क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं। 1986 में मुंबई में विषाक्त कफ सीरप से 14 बच्चों की जान गई थी और दिल्ली में 33 बच्चों की।

"इसके बाद 2020 में जम्मू में 12 बच्चों की मौत हुई। हर बार सब कुछ ठीक करने की बातें की गईं, लेकिन स्थितियां नहीं बदलीं। 2022 में भारतीय दवा कंपनियों की ओर से बनाई गई कफ सीरप से गांबिया और फिर उज्बेकिस्तान में कई बच्चों की मौत हुई। इन मौतों का संज्ञान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लिया।

इन मामलों के कारण भारत की दवा कंपनियों की बदनामी भी हुई। माना जा रहा था कि इस बदनामी के कारण विषाक्त कफ सीरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली सरकारी एजेंसियां अपना काम सही तरह से करेंगी, पर नतीजा ढाक के तीन पात वाला रहा।

गांबिया और उज्बेकिस्तान को कफ सीरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई तो हुई, पर ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो नजीर बनती और विषाक्त कफ सीरप बनने का सिलसिला थमता। ऐसा ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनी के साथ हो तो हैरानी नहीं, क्योंकि इस सीरप में विषाक्त रसायन के प्रयोग को लेकर विरोधाभासी खबरें आ रही हैं।

दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी गुणवत्ता की परख करने वाली सरकारी एजेंसियां और सरकारें कुछ भी दावा करें, यह काम सही तरह नहीं होता और इसका प्रमाण यह है कि आए दिन दवाओं के सैंपल फेल होने की खबरें आती हैं। पिछले महीने खबर आई थी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों की 94 दवाओं के सैंपल फेल हुए। जांच में तीन दवाएं नकली भी निकलीं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन हर माह ड्रग अलर्ट जारी करता है। अगस्त के ड्रग अलर्ट के अनुसार हिमाचल की 31 दवा कंपनियों की 38 दवाएं गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं उतरीं। इसी ड्रग अलर्ट के अनुसार उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश की दवा कंपनियों में बनीं 56 दवाओं के सैंपल भी फेल हुए। जुलाई के ड्रग अलर्ट के अनुसार कुल 143 दवा नमूने फेल पाए गए। जून के ड्रग अलर्ट में कुल 188 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इनमें हिमाचल, गोवा और महाराष्ट्र की दवा कंपनियों की दवाएं थीं।

इस पर संतोष नहीं जताया जा सकता कि ये सैंपल बैच विशेष के होते हैं और उन्हें हटाने को कहा जाता है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि दोयम दर्जे की दवाओं को हटाने के निर्देश जारी करने के पहले वे मरीजों तक नहीं पहुंच जाती होंगी। चूंकि हिमाचल फार्मा कंपनियों का गढ़ है, इसलिए दवाओं के फेल सैंपल के मामले में यहां की कंपनियों का नाम खूब आता है, पर सच यह है कि शेष देश की दवा कंपनियों के सैंपल भी फेल होने का सिलसिला कायम है। भारत ने जेनेरिक दवाओं के निर्माण में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन यदि दोयम दर्जे की दवाएं बनती रहीं तो यह पहचान खतरे में पड़ सकती है।

क्या हम केवल दवाओं की गुणवत्ता ही बनाए रख पाने में नाकाम हैं? नहीं। दवाओं के साथ-साथ खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों की गुणवत्ता के मामले में भी हमारी स्थिति दयनीय है। डिब्बाबंद खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में रहती है। उनके निर्माण में मानकों का उल्लंघन होता ही रहता है। कई बार तो उनमें विषाक्त अखाद्य वस्तुओं की भी मिलावट की जाती है, लेकिन मुश्किल से ही कोई मिलावटखोर दंडित होता है।

जिस तरह दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सरकारी एजेंसियां और ड्रग इंस्पेक्टर अपना काम ले-देकर करते हैं, उसी तरह खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता की परख करने वाली सरकारी एजेंसियां और फूड इंस्पेक्टर भी। सरकारी तंत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का ही यह नतीजा है कि भारत में न तो दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित है और न ही खाद्य एवं पेय पदार्थों की। दूध, खोया, मिठाई, मसालों आदि में तो मिलावट की आशंका बनी ही रहती है और अक्सर यह सही पाई जाती है।

दवाएं हों या खाद्य एवं पेय पदार्थ या फिर अखाद्य वस्तुएं, अपने देश में सबके निर्माण के लिए मानक बने हुए हैं और सबकी गुणवत्ता परीक्षण के नियम-कानून हैं, लेकिन उनका सही तरह पालन नहीं होता। जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार होना एक अलिखित नियम सा बन गया है। इसी तरह जहां कहीं भी सरकारी अनुमति, संस्तुति, परीक्षण आदि की आवश्यकता होती है, वहां भी मानकों की अनदेखी के साथ नियम-कानूनों का उल्लंघन होता है।

हैरानी नहीं कि बहुत कम भारतीय उत्पाद ऐसे हैं, जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चूंकि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए वे विश्व बाजार में अपनी छाप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी कारण हम आत्मनिर्भर बनने के अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। स्वदेशी के सहारे स्वावलंबी बनने की यात्रा तब पूरी होगी, जब हमारे हर तरह के उत्पाद भरोसेमंद होंगे। अच्छा हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगने का थोथा दावा आत्मनिर्भरता की राह की आत्मघाती बाधा है।

जीएसटी 2.0 - भारत में वस्त्र क्षेत्र के सपनों को वास्तविकता में बदलने परिवर्तन का एक सूत्र

गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री

1 जुलाई, 2017को भारत में दशकों का सबसे साहसिक आर्थिक सुधार हुआ। मानसून कीउस एक सुबह, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 17 अलग-अलग करों और 13 उपकरों को एक एकीकृत ढांचे के साथ बदल दिया, जिससे मूल रूप से देश की राजकोषीय संरचना को नया आकार मिला। यह केवल एक कर सुधार नहीं था, यह एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की ओर भारत की साहसिक यात्रा की शुरुआत थी।

आठ साल बाद अब यह परिवर्तन किसी असाधारण घटना से कम नहीं लगता है। कर संग्रह 2017-2018 के 7.19 लाख करोड़ रुपये से तीन गुना बढ़कर 2024-2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ तीन गुना हो गया है। इसके साथ ही करदाताओं का आधार 65 लाख से दोगुना होकर 1.5 करोड़ हो गया है, जिससे लाखों लघु उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सका है। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए, भारत ने अब 22 सितंबर, 2025से अगली पीढ़ी के जीएसटी युग में प्रवेश कर लिया है, जिसमें इस प्रणाली को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में सुव्यवस्थित कर दिया गया है, साथ ही इसमें 40 प्रतिशत की स्लैब लग्जरी और डिमेरिट वस्तुओं के लिए रखी गई है।

घरों में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, दवाओं और शिक्षा सामग्री की आपूर्ति पर 0 से 5 प्रतिशत के बीच कर लगने से परिवारों को अधिक बचत होगी, जबकि किसानों को ट्रैक्टरों, टायरों, कीटनाशकों और सिंचाई उपकरणों पर कम जीएसटी लगने से अधिक लाभ प्राप्त होगा जिससे इनपुट लागत में कमी आएगी और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर को भी इससे बड़ी राहत मिली है क्योंकि स्कूटर और कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। अब 2,500 रुपये तक की कीमत वाले (पहले 1,000 रुपये) रेडीमेड कपड़ों पर भी केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। मैंने एक कॉलेज छात्र से बातचीत की और जब उससे कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने कहा, अब त्योहारों की खरीदारी ने मेरी जेब पर पड़ने वाले बोझ को बहुत कम कर दिया है। अब उसी बजट से मैंने एक की बजाय दो ट्रेंडी शर्ट खरीदीं हैं। मुझे जीएसटी स्लैब के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अब कपड़े खरीदना अधिक सस्ता हो गया है। इसके विपरीत, पान मसाला, तंबाकू, ऑनलाइन गेम्स, लग्जरी एसयूवी और कैसिनो जैसे लग्जरी और डिमेरिट सामान अब 40 प्रतिशत स्लैब के अंतर्गत आते हैं। इस सुधार ने 'फिट इंडिया,हेल्दी इंडिया'के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए उत्तरदायी उपभोग को बढ़ावा दिया है, जो बचत का एक वास्तविक स्वरूप है। और जैसे इन सुधारों से परिवारों, किसानों और उद्योगों को राहत मिलती है, वैसे ही ये हमारे वस्त्र क्षेत्र को भी नई ताकत देते हैं। जीएसटी 2.0वस्त्र उद्योग के पूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है और आत्मनिर्भर भारत का एक जीवंत उदाहरण है।

भारत में वस्त्र उद्योग बहुत बड़ा है, जो आजीविका और निर्यात दोनों को प्रभावित करता है।आज, इस उद्योग का आकार 179 बिलियन डॉलर है और यह 4.6 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। अब सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस उद्योग के आकार को लगभग दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर करना है, जिससे देश भर के परिवारों के लिए रोजगार और आय के और भी अधिक और नए अवसर पैदा होंगे। भारत का संगठित घरेलू वस्त्र बाजार लगभग 142 से 145 बिलियन डॉलर का है और जब हम इसमें बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र को शामिल करते हैं, तो यह 155 से 160 बिलियन डॉलर के करीब हो जाता है। करों की दर को युक्ति संगत बनाने जैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत के साथ एवं फाइबर-तटस्थ व्यवस्था को अपना कर निर्माता अब बचत का लाभ सीधे खरीददारों को दे सकते हैं। उपभोक्ताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए, जिनका 2047 तक भारत के लक्षित उपभोक्ता आधार का 60 प्रतिशत बनाने की उम्मीद है उनके लिए ये सुधार सबसे बड़ा लाभ लाएंगे। निम्न आय समूहों के साथ मिलकर, स्थानीय उद्योग को समर्थन देते हुए आवश्यक वस्त्रों के अधिक किफायती बनने से हर साल लगभग 8 से 10बिलियन डॉलर की बचत होने का अनुमान है। ये सुधार कीमतों को कम करने से कहीं बढ़ कर है और यह सही मायनों में फैशन को और अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रतिनिधित्व करता है।

वस्त्र क्षेत्र के लिए जीएसटी 2.0 के सबसे बड़े बदलावों में से एक लंबे समय से चले आ रहे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है, जिसने मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र को कमजोर कर दिया था। इससे पहले, मानव निर्मित रेशों पर 18 प्रतिशत, सूत पर 12 प्रतिशत और कपड़ों पर केवल 5 प्रतिशत कर लगाया जाता था। इस संरचना ने कच्चे माल को तैयार उत्पादों की तुलना में महंगा बना दिया, जिससे कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो गई और नया निवेश बाधित हुआ। जीएसटी 2.0 में अब मानव निर्मित क्षेत्र में एक समान 5 प्रतिशत कर है, जो सही अर्थों में फाइबर तटस्थ इकोसिस्टम सृजित कर रहा है। लाखों एमएसएमई के लिए, जो भारत के वस्त्र उद्योग का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं, यह एक बड़ी राहतहै। यह मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र के लिए वैश्विक केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को मजबूत करता है और प्रतिवर्ष उत्पादित 22,000 मिलियन परिधानों को कम इनपुट लागत, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और अधिक बाजार मांग के साथ निर्मित करने में सक्षम बनाता है। यह सुधार न केवल कपड़ों को सस्ता बनाएगा और निर्यात को बढ़ावा देगा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूत करेगा, जो हमारी विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ाएगा।

एक उदाहरण से इसे समझते हैं। इससे पहले सूरत में महिलाओं की सिलाई इकाई में मानव निर्मित फाइबर और धागे की लागत इतनी अधिक थी कि उनका लाभ मार्जिन कम हो जाता था और ऑर्डर अक्सर विदेशों में चले जाते थे। अब, जीएसटी 2.0 द्वारा करों को घटाकर एक समान 5 प्रतिशत करने के साथ, उनकी निवेश लागत कम हो गई है, वे अधिक ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, उचित मजदूरी का भुगतान कर सकते हैं और यहां तक कि अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। इस तरह एक राष्ट्रीय सुधार सीधे आम श्रमिकों और परिवारों के जीवन को प्रभावित करता है।

यह लाभ यहीं खत्म नहीं होते। वाणिज्यिक माल वाहनों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत तथा लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से वस्त्र आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन लागत कम हो जाती है। यह सीधे तौर पर पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का सहयोग करता है और साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्र निर्यात को मजबूत बनाता है। जीएसटी 2.0के सुधार एक साथ मिलकर वस्त्र मूल्य श्रृंखला के हर चरण को सशक्त बनाते हैं जैसे फाइबर बनाने से लेकर तैयार परिधान और विदेशी बाजार भेजने तक। इससे देश भर में विकास और रोजगार का सृजन होता है।

जीएसटी 2.0 का आर्थिक प्रभाव आम परिवारों के रोजमर्रा के जीवन में महसूस किया जा रहा है।उद्योग जगत का अनुमान है कि इससे प्रत्यक्ष उपभोग में लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, तथा दरों में कमी के कारण परिवारों को प्रतिवर्ष लगभग 48,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, 2014 में यूपीए सरकार के तहत, दैनिक जरूरतों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने वाले एक परिवार ने लगभग 25,000 रुपये कर का भुगतान किया था। जीएसटी और जीएसटी 2.0के बाद आज वही परिवार लगभग 5,000 रुपये से 6,000 रुपये का कर भुगतान करता है।यानी हर साल लगभग 20,000 रुपये की बचत होती है और यह पैसा बच्चों की शिक्षा, बेहतर पोषण और परिवार के कल्याण के लिए वापस परिवार के पास जाता है। आयकर छूट के साथ मिलकर सभी भारतीय परिवारों के प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है।छोटे शहरों और गांवों में इसका प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जहां भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी रहती है।

बेगूसराय में बाजारों की अपनी हाल के दिनों की यात्रा के दौरान, मैंने जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभावको देखा। खुदरा विक्रेताओं ने कम दरों को ले कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और ग्राहकों में इन सुधारों को ले कर उत्साह साफझलक रहा था, क्योंकि त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करने के लिए ग्राहक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बाजारों में ग्राहकों की बढ़ती भीड़ से स्पष्ट है कि ये सुधार किस प्रकार एक जीवंत और सकारात्मक आर्थिक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, जो परिवारों और व्यवसायों दोनों के लिए वास्तविक लाभ है। मासिक जीएसटी संग्रह जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1.85 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था, अब लगातार 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इन सुधारों से न केवल नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है, तथा इन कम दरों पर भी राजस्व में वृद्धि जारी रहेगी। यह एक दुर्लभ अवसर है, जहां सुधार जन-केंद्रित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं, जो परिवारों को मजबूत बनाते हुए भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं।

जीएसटी 2.0 के वस्त्र क्षेत्र के सुधार सिर्फआर्थिक परिवर्तन से कहीं अधिक हैं, वे समावेशी विकास के बारे में हैं, जिनका सीधा प्रभाव पूरे भारत के 65 लाख बुनकरों और कारीगरों पर पड़ रहा है।इससे न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है बल्कि इस क्षेत्र में काम करने वाली लाखों महिलाओं की आजीविका को भी सहारा मिलता है। हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से यह पारंपरिक उत्पाद अब भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। साथ ही,सिलाई मशीनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना भारत के महिला प्रधान वस्त्र क्षेत्र को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दे रहा है।

पिछले दशक में ग्रामीण आय और व्यय दोगुना से अधिक हो गया है, जो 2011-12 के 1,430 रुपये प्रति माह से बढ़कर 2023-24 में 4,122 रुपये हो गया है। जीएसटी 2.0 के साथ, इस बढ़ती क्रय शक्ति से सीधे भारतीय निर्मित कपड़ों की मांग तेज होगी, जिससे बुनकरों, दर्जनों और परिधान कामगारों के लिए अधिक कार्य सृजित होंगे और इससे विकास का एक चक्र उत्पन्न होगा जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होगा।

हाल ही में एक कार्यक्रम में, मेरी मुलाकात कई स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) दीदियों से हुई, जिन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने पहले उन्हें लखपति दीदी बनाकर उन्हें सशक्त बनाया और अब जीएसटी सुधारों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को अधिक किफायती बनाकर तथा आयकर सुधारों के माध्यम से उनके कर के बोझ को कम किया है। उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली उनके परिवारों के लिए अधिक उपहार और आनंदमय उत्सव के साथ वास्तविक खुशी ले कर आई है। ये सुधार अर्थव्यवस्था को तेज गति दे रहे हैं, आय बढ़ा रहे हैं और कर का बोझ कम कर रहे हैं।

ऐसे समय में जब भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा हैतबहथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र,हमारी स्वयं सहायता समूह दीदियों के साथ मिलकर वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी आंदोलन की आत्मा के रूप में खड़ा है। हमारे कारीगर और बुनकर केवल इन परंपराओं को संरक्षित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की ओर देश की यात्रा का वास्तविक आधार भी हैं।

जीएसटी 2.0 और विकसित भारत 2047 की राह

जैसे-जैसे भारत अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 2047 की तरफ आगे बढ़ रहा है, जीएसटी 2.0 केवल कर सुधार के रूप में ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए विकास की रणनीति के रूप में भी हमारे सामने खड़ा है। टैक्स स्लैब को सरल बना कर, आम जन के पारिवारिक खर्चों को कम करके,किसानों को सशक्त बनाकर, एमएसएमई को सहायता प्रदान करके और वस्त्र जैसे श्रम-गहन उद्योगों को पुनर्जीवित करने से ले कर यह जीवन की सुगमता और व्यापार करने में आसानी दोनों को मजबूत करता है। फाइबर-न्यूट्रल जीएसटी विशेष रूप से परिवर्तनकारी है, जो मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्त्रों में नई वृद्धि को बढ़ावा देगा, इसके साथ ही भारत को वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने, लाखों नए रोजगार सृजित करने और परिधान तथा घरेलू साज-सज्जा के क्षेत्र में एक सच्चे वैश्विक अग्रज के रूप में उभरने में सक्षम बनाएगा। जैसा कि जीएसटी 2.0 इस नवरात्रि में लागू हो गया है, यह परिवारों के लिए बचत,किसानों के लिए राहत, व्यवसायों में वृद्धि और श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए दिवाली से पहले मिला एक वास्तविक उपहार है। संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला की ओर से, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरलता, निष्पक्षता और विकास की ओर ले जाने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जीएसटी 2.0 हमारी सुधार यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होने का रोडमैप निर्धारित करता है।

भारत के लिए अवसर और चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा

राजीव शुक्ला

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा संकट बार-बार सामने आता है जिसे 'किंडलबरगर ट्रैप' कहा जाता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री चार्ल्स किंडलबरगर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि जब कोई महाशक्ति वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व छोड़ देती है और कोई नई शक्ति उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे नहीं आती, तो पूरी दुनिया अराजकता के चंगुल में फंस जाती है।

बीसवीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन कमजोर हो चुका था, अमेरिका तैयार नहीं था और नतीजा यह हुआ कि महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी आपदाएं दुनिया पर टूट पड़ीं। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ऊब का शिकार और घरेलू स्तर पर विभाजित है। चीन आधा-अधूरा और अविश्वसनीय नेतृत्व पेश कर रहा है। यूरोप अपने संकट में उलझा हुआ है। सवाल यह है कि इस बार वैश्विक व्यवस्था को अराजकता में जाने से कौन बचाएगा। क्या भारत इस खालीपन को भर सकता है?

भारत के पास आज वह पूंजी है, जो शायद किसी और देश के पास नहीं। आधे से अधिक भारतीय तीस वर्ष से कम आयु के हैं। जब पूरी पश्चिमी दुनिया वृद्ध होती आबादी से जूझ रही है और चीन जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, तब भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति उसे भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बना सकती है।

यह युवा शक्ति केवल श्रम नहीं है। यह विचार, नवाचार और डिजिटल ऊर्जा का भी स्रोत है। हालांकि यही युवा पीढ़ी रील, वीडियो और तात्कालिक प्रसिद्धि के आकर्षण में उलझकर अपनी दिशा खो सकती है। अगर युवा शक्ति को जिम्मेदारी की ओर मोड़ी जाए, तो भारत न केवल खुद को, बल्कि पूरी दुनिया को किंडलबरगर ट्रैप से निकाल सकता है।

भारत की ताकत उसकी विविधता है। भाषाओं, पंथों, जातियों और संस्कृतियों की अनगिनत परतों के बावजूद इस देश ने लोकतंत्र को जीवित रखा है। यही माडल दुनिया को चाहिए, क्योंकि पश्चिम में पहचान की राजनीति और राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और चीन अधिनायकवादी प्रणाली थोपना चाहता है। भारतीय प्रवासी समुदाय इस संभावना को गहराई देता है। फ्रांस में ओणम के उत्सव से लेकर ब्रिटेन में गणपति विसर्जन की तस्वीरें भारत

की साफ्ट पावर बढ़ाती हैं, जो उसे दूसरों से अलग करती है। फिर भी भारत के सामने सबसे बड़ी कसौटी लोकतांत्रिक विरोधाभास की है।

भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज कहता है, पर घरेलू स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। यदि भारत वैश्विक नेतृत्व का चेहरा बनना चाहता है, तो उसे घर के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा। भरोसेमंद नेतृत्व के बिना आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होता। विश्वास, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था ही दुनिया को अराजकता से बचा सकते हैं।

भारत की मौजूदा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बड़े दावे किए हैं जैसे जी-20 की अध्यक्षता और 'विश्वगुरु' बनने का सपना, लेकिन देश के भीतर कई कमजोरियां इस दावे को कमजोर करती हैं। चुनावी प्रक्रिया में पैसे का बढ़ता दबाव, मीडिया की आजादी पर उठते सवाल और स्वतंत्र संस्थाओं पर राजनीतिक प्रभाव देश की लोकतांत्रिक छवि धूमिल करते हैं।

जलवायु बदलाव से निपटने के वादे भी अक्सर बड़े उद्योगों को रियायत देने में खो जाते हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सरकार का खर्च अभी भी बहुत कम है। विदेश नीति में भी कभी-कभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अचानक बदलाव दिखता है, जिससे भरोसे की कमी महसूस होती है। यदि सरकार घर के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत नहीं करती, तो दुनिया में भारत की नेतृत्वकारी छवि सिर्फ भाषणों तक सिमट जाएगी। भारत की सबसे बड़ी संभावना उसका टेक्नो-डेमोक्रेटिक माडल है। यूपीआइ ने दिखा दिया कि डिजिटल लेनदेन को कैसे आम आदमी के लिए सहज और सुलभ बनाया जा सकता है। आधार ने पहचान को डिजिटल रूप दिया, कोविड के दौरान कोविन प्लेटफार्म ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वास्थ्य प्रबंधन में तकनीक का उपयोग पारदर्शी और कुशल तरीके से किया जा सकता है।

यह सब केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं थीं, यह उस सोच का परिचय थी, जिसमें तकनीक को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि भारत यही माडल दुनिया को दे, तो वह चीन के तकनीकी अधिनायकवाद और पश्चिम के लाभ केंद्रित पूंजीवाद के बीच एक नया संतुलित विकल्प पेश कर सकता है।

हालांकि केवल विकल्प पेश करना पर्याप्त नहीं। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वैश्विक व्यवस्था को केवल किसी के आर्थिक हितों की नहीं, बल्कि सार्वजनिक वस्तुओं की जरूरत होती है। जैसे जलवायु वित्त, महामारी प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और मानवीय संकटों में सहयोग। भारत ने हाल के वर्षों में यह दिखाने की कोशिश की है कि वह इस भूमिका के लिए तैयार है, पर ऐसे प्रयास निरंतरता मांगते हैं। भारत को लगातार यह साबित करना होगा कि वह केवल अवसर की राजनीति नहीं करता, अपितु संकट की घड़ी में भी वैश्विक भरोसा कायम कर सकता है।

अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और साइबर स्पेस में संघर्ष भविष्य का सबसे बड़ा तनाव बनेगा। जलवायु परिवर्तन और प्रवासन से पैदा हुए संकट इस तनाव को और गहरा करेंगे। आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटने पर विकासशील देशों को बड़ा झटका लगेगा। यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध से भी जटिल हो सकती है, क्योंकि अब संघर्ष केवल सैन्य या विचारधारा का नहीं होगा, बल्कि तकनीक, स्वास्थ्य, जलवायु और आर्थिकी एक साथ उलझेंगे। यही समय है जब भारत खुद को तीसरे ध्रुव के रूप में पेश करे। जिस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बीसवीं सदी में एशिया-अफ्रीका को एक अलग आवाज दी, वैसे ही इस सदी में भारत तकनीक और लोकतंत्र के एजेंडे पर दुनिया को एक नया विकल्प दे सकता है। इसके लिए उसे केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक नेतृत्व दिखाना होगा। इतिहास हमेशा मौके की कसौटी पर नेताओं और राष्ट्रों को परखता है।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

खास खबर

स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन 13 अक्टूबर तक आमंत्रित

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कण्डिका 06 (1) (क) को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने की अनुमति दी गई है। स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों की पूर्ति 13 अक्टूबर 2025 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश की जानकारी, सूचना पत्र के साथ विभाग की वेबसाइट eduportal.cg.nic.in में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अहिवारा विधानसभा में 10 ओपन जिम निर्माण के लिए 60 लाख स्वीकृत

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत् प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड धमधा में 10 निर्माण कार्यों के लिए 60 लाख रूपए की स्वीकृत दी है। जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा किया जाएगा। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विख धमधा के ग्राम पंचायत एवं ग्राम कोड़िया, नारधा, खपरी (कु), अहेरी, सांकरा, पाहरा, ओखरा, बागडूमर, पोटिया एवं मोहंदी सहित 10 ग्रामों में ओपन जिम निर्माण हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए 6–6 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

विकास कार्य के लिए 15 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य के लिए 15 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद विजय बघेल द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन नगर निगम भिलाई द्वारा किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत सेक्टर–7 वेस्ट वार्ड, कल्याण महाविद्यालय में सामुदायिक पेयजल प्लांट, 1000 एलपीएच प्लांट, 1000 इंसुलेटेड एसएस टैंक स्थापना के लिए 15 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

निगम आयुक्त ने निर्माणाधीन एमआरएफ प्लांट व पीएम आवास का किया औचक निरीक्षण

■ **समय सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश**

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 02 वैशालीनगर अंतर्गत निर्माणाधीन एमआरएफ प्लांट, एसएलआरएम सेंटर एवं जोन 1 खम्हरिया प्रधानमंत्री आवास का आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा निरीक्षण किया गया। निगम आयुक्त द्वारा जामुल ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के समीप निर्माणाधीन मटेरियल रिकवरी फैसेलिटी (रूक्रन्न) प्लांट का निरीक्षण कर कार्य गुणवत्ता एवं समयावधि का विशेष ध्यान रखे जाने हेतु उप अभियंता अर्पित बंजारे एवं एजेंसी अनुराग शर्मा को निर्देशित किये हैं। गोठान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कुछ मवेशियों को शिफ्टिंग के संबंध में भी जोन आयुक्त ऐशा लहरे के साथ चर्चा की गई।

निगम आयुक्त द्वारा समीपस्थ एसएलआरएम सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। कार्यरत स्वच्छता दीदियों के उपस्थित रजिस्टर का अवलोकन किया गया। कार्य की आवश्यकता और मांग के अनुरूप दीदियों के नियोजन किये जाने के संबंध में सुझाव दिये, जिससे व्यय के अनुरूप कार्य का सही प्रबंधन किया जा सके। कुरूद कैलाश नगर स्थित कृष्णकुंज उद्यान के समीप निगम का रिक्त भूमि है, उक्त स्थल में तार से फेंसिंग कर पौधारोपण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी प्रकार जोन 1 अंतर्गत खम्हरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण किया गया है। जहां कुछ परिवार निवास करना प्रारंभ कर दिए हैं, निर्माणकर्ता एजेंसी को मकान का कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया गया है। निर्माण कार्य अंतिम स्थिति में है, जल्द ही लोगों को बकाया आवास मिलेगी। इस दौरान आवास निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता दीपक देवांगन, आदित्य सिंह एवं एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अवैध नल कनेक्शन पाये जाने पर होगी विच्छेदन की कार्यवाही

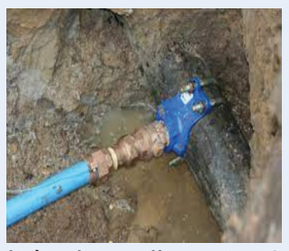

नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2025 को सर्व सम्मति से यह संकल्प पारित किया गया था, कि निगम क्षेत्र के अवैध नल कनेक्शनधारी 31 अक्टूबर 2025 के भीतर जोन कार्यालय में जाकर नल संयोजन शुल्क तथा शास्ति शुल्क 3000.00 रूपये जमा कर अपने अवैध नल कनेक्शन को नियमित करा सकेगें। निगम द्वारा दिए गए समय पर जिन नल कनेक्शनधारियों द्वारा शुल्क जमा नहीं किये हैं और नल कनेक्शन नियमित नहीं कराए है। उन सभी कनेक्शनधारियों के घरो का सर्वे कर जांच की जाएगी। जांच में यदि अवैध नल कनेक्शन पाया जाता है, तो बिना पूर्व सूचना दिये नल विच्छेदन की कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं जल उपभोक्ता की होगी।

निगम ने बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करने पर दुकान को किया सील

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 04 अंतर्गत पुरानी बस्ती छावनी निवासी रामाधार सिंह द्वारा अपना दुकान विवेक ट्रेडर्स को किराये पर दिया है, जहां कबाड़ का सामान रखकर दुकान संचालित किया जा रहा था। पूर्व में मकान मालिक द्वारा 3 वर्ष का बकाया संपत्तिकर 69781 रूपये का चेक दिया गया था, बैंक खाते में राशि की अनुपलब्धता के कारण चेक बाउंस हो गया। मकान मालिक को सूचना देकर बताया गया कि चेक बाउंस हो गया है, उसके बाद भी राशि जमा नहीं किया गया। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की दल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही के संबंध में मकान मालिक को बकाया संपत्तिकर जमा करने समझाइस दी गई और कुर्की कार्यवाही के संबंध में पढ़कर सुनाया गया। इसके पूर्व भी बकाया संपत्तिकर जमा करने के संबंध में नोटिस दिया गया था। बकाया राशि जमा नहीं करने पर 2 दुकानों में से 1 दुकान को सील बंद की कार्यवाही कर निगम के अधीन लिया गया। साथ ही अन्य दुकानों को मिलाकर लगभग 1.80 लाख रूपये की बकाया संपत्तिकर वसूल किया गया है। कुर्की के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, बसंत देवांगन, विजेन्द्र परिहार, वत्सल, विनोद वर्मा, गंगा चौहन सहित एसपीएस एजेंसी के कर्मचारी उपस्थित रहे।

निगम क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में होगा पेंशनर का वार्षिक सत्यापन

भिलाई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित केन्द्र पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन मोबाईल एप Beneficiary Satyapan App (लाभार्थी सत्यापन एप) के माध्यम से कराया जाना है। इसके लिए निगम मुख्य कार्यालय सभागार में 155 आंगनबाड़ी कार्यकताओं को योजना के नोडल अधिकारी नरेन्द्र कुमार बंजारे एवं प्रोग्रामर दिप्ती साहू के निर्देश पर कम्प्युटर आपरेटर अंजू साहू द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। जो अपने आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन मोबाईल एप से करेंगी। इस योजना के पेंशन हितग्राही अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सत्यापन करा सकते है। नगर पालिक निगम भिलाई पेंशन हितग्राहियों से अपील करती है कि जल्द से जल्द अपने वार्ड के आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर सत्यापन का करवा लें।

हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में सड़कों पर नुकीले पिंजरे वाले ट्रैक्टर चलाने पर रोक

■ **नियम का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी चालानी कार्यवाही**

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के परिपालन में जिले में नुकीले पिंजरे वाले दोहरे पहिए लगे ट्रैक्टरों को सड़क पर चलाने पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि नुकीले पिंजरे वाले दोहरे पहिए लगे ट्रैक्टरों का उपयोग किसानों द्वारा केवल खेतों में कृषि कार्य हेतु किया जाता है। परंतु कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले इन ट्रैक्टरों को पिंजरे वाले पहिये हटाए बिना ही, अनाधिकृत और लापरवाही पूर्ण तरीके से सामान्य सड़कों, सीमेंट की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाया जा रहा हैं। जो कि मोटर वाहन अधिनियम/नियमों का उल्लंघन है और इससे गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है।

जिला क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा क्षेत्र के किसानों से अपील की गयी है कि उक्त वाहनों को उपयोग सिर्फ खेतों में करे, ना कि सड़क/सीमेंट की सड़कों पर, ताकि दुर्घटनाओं और कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके। किसी भी ट्रेक्टर चालक या मालिक द्वारा इस नियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर उसके खिलाफ कड़ी चालानी कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है साथ ही चालकों व वाहन स्वामियों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में रणनीति 2025 - निदेशक कप का उद्घाटन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 07 अक्टूबर 2025 को रणनीति 2025 ङ्क निदेशक (कार्मिक) कप (स्टेज–1) का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों के प्रबंधकीय एवं रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करना है।

इस प्रतियोगिता में कुल 31 टीमों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें एसएसपी की तीन टीमें भी शामिल थीं। प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात 27 टीमें क्रमशः 14 एवं 13 टीमों के दो समूहों में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक (खदान) श्री बी. के. गिरी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के लिए संकाय सहयोग सहायक निदेशक (एआईएमए) श्री सी. एस. रस्तोगी, एवं प्रबंधक (एआईएमए) श्री प्रदीप कुमार, द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस आयोजन का समन्वयन कार्यकारी महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन ङ्क एल एंड डी) श्री मुकुल कुमार सहारिया के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

अपने उद्घाटन संबोधन में श्री बी. के. गिरी ने वर्तमान के गतिशील व्यावसायिक परिवेश में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रणनीति जैसी पहल प्रतिभागियों को वास्तविक जीवन की प्रबंधन चुनौतियों का अनुकरण करते हुए विश्लेषणात्मक सोच, निर्णय क्षमता एवं नेतृत्व गुणों को विकसित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यावसायिक सिमुलेशन आज के प्रतिस्पर्धी युग में भविष्य के प्रबंधकीय नेतृत्व को दिशा देने का सशक्त माध्यम हैं।

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा, अफसरों को निर्देश

■ **मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा पंचायतों में संचालित निर्माण कार्यों पर चर्चा**

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा पंचायतों में संचालित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुमोदित लेबर बजट और मानव दिवस सृजन व युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 की कार्य योजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये गये। जिले की कुल 300 ग्राम पंचायतों में से 92 जल संकट ग्रसित, 166 अर्द्ध जल संकट ग्रसित तथा 42 ग्रीन ज़ोन क्षेत्र के रूप में केंद्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा चिन्हांकित किये गये हैं। अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों की कार्य योजना में इन क्षेत्रों को सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये। युक्तधारा पोर्टल पर दो श्रेणियों में कार्य प्रस्तावित हैं। पहली श्रेणी में वृक्षारोपण, तालाबों में मछली पालन, रिचार्ज पिट और नाली निर्माण जैसे कार्य शामिल होंगे, वहीं दूसरी श्रेणी में पशु शेड, आंगनबाड़ी भवन, मुक्तिधाम शेड जैसे निर्माण कार्य रखे जायेंगे। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन कार्यों की योजना तैयार करने को कहा गया है।

बैठक में सीईओ बजरंग दुबे ने बताया कि जिले में अब तक 130 अमृत सरोवर निर्माण किए जा चुके हैं, जिनमें से 69 में आजीविका गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। शेष सरोवरों में शीघ्र आजीविका गतिविधियाँ जैसे मत्स्य पालन, बत्तख पालन और सिंघाड़ा उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए गए। स्व–सहायता समूहों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले में जनपद पंचायत धमधा के 889, दुर्ग के 283 और पाटन के 431 कुल मिलाकर 1603 आवास अपूर्ण हैं। जनपद धमधा द्वारा 20 अक्टूबर 2025 तक 300, दुर्ग द्वारा 150 तथा पाटन द्वारा 300 आवास पूर्ण करने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने सभी आवासों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिये। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के 649 अप्रारंभ आवासों को अक्टूबर 2025 के अंत तक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत कुल 212 छत स्तर आवासों को अक्टूबर माह के अंत तक, 279 छत स्तर आवासों को नवंबर के अंत तक तथा 207 लिंटल स्तर आवासों को दिसंबर के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गये हैं। साथ ही 1952 (2024–25), 1097 (2025–26) तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के 648 अपात्र हितग्राहियों की सूची को अपीलीय समिति की स्वीकृति के पश्चात राज्य कार्यालय को भेजने हेतु निर्देश दिये गये।

सभी जनपदों को आर–सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से रूरल मेसन ट्रेनिंग के लक्ष्यों को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण करने को कहा गया है। जिन हितग्राहियों का एनपीसीआई मैपिंग नहीं हो पाया है, उनके बैंक खातों का मैपिंग कार्य तीन दिवस के भीतर पूर्ण करने हेतु संबंधित सचिव, नोडल अधिकारी एवं रोजगार सहायकों की ड्यूटी लगाने को कहा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहान मॉडल सीएलएफ को वितरण केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही सीएमटीसी (कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर) के लिए 15 दिवस में भवन चयन कर उसे स्थापित करने तथा जीआरसी (जेंडर रिसोर्स सेंटर) की स्थापना हेतु दुर्ग एवं पाटन जनपद में भवन चयन कर खाता खोलने व स्क्रीनिंग कमेटी से स्वीकृति प्राप्त करने को कहा गया।

लखपति महिला पहल योजना अंतर्गत वर्ष 2025–26 में प्राप्त 42664 लक्ष्यों की त्रैमासिक आय प्रविष्टि आजीविका सीआरपी के माध्यम से समय पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले और जनपद स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी 10 प्रतिशत लखपति दीदी की गणना का भौतिक सत्यापन भी करें। समीक्षा बैठक में सामुदायिक शौचालयों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। कुल 433 स्वीकृत शौचालयों में से 419 पूर्ण हो चुके हैं जबकि 09 कार्य प्रगति पर हैं। दुर्ग जनपद के ग्राम झोला एवं धमधा जनपद के ग्राम ढौर (खे) में शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है, जिसकी राशि पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा खर्च कर ली गई है। कलेक्टर ने इस संबंध में वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही 404 पूर्ण हो चुके सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील रखने व समूहों को संचालन हेतु सौंपे जाने के निर्देश भी दिए गये। हॉट बाजार एवं मुख्य राज्य मार्गों के समीप आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन कर नये शौचालय निर्माण के प्रस्ताव भेजने तथा उन्हें आजीविका से जोड़ते हुए संचालन की कार्य योजना बनाकर एमओयू प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गई।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घर–घर कचरा संग्रहण और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले के 381 ग्रामों में यह कार्य किया जा रहा है। इनमें से 165 ग्रामों में यूज़र चार्ज वसूला जा रहा है जिससे 42.42 लाख रुपये की आय हुई है। प्लास्टिक विक्रय से 0.66 लाख की अतिरिक्त आय हुई है। 369 ग्रामों में स्वच्छाग्राही समूहों को सेवा शुल्क प्रदान किया जा रहा है।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर...

2028-29 तक पूरा छत्तीसगढ़ होगा बाल विवाह मुक्त

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाना है। यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकल्प है। इसी दिशा में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले की 225 ग्राम पंचायतों में पिछले दो वर्षों से कोई बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ है। इन्हें बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2025 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में समुदाय और प्रशासन की संयुक्त भूमिका अहम है।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता और निगरानी के माध्यम से प्रदेश को चरणबद्ध तरीके से बाल विवाह मुक्त बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, जबकि सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतें भी बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुकी हैं। इन उपलब्धियों ने सिद्ध किया है कि समाज और सरकार की साझेदारी से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य शीघ्र ही साकार होगा।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, कोंडागांव ने जूडो में लहराया परचम

रायपुर। दुर्ग में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय, कोंडागांव (बस्तर संभाग) के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और जिले का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित किया है। विद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित कर बस्तर संभाग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पूरे बस्तर संभाग को कुल 21 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, जिनमें से अकेले स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, कोंडागांव के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण पदक हासिल किए। यह उपलब्धि विद्यालय के खेल प्रशिक्षण और विद्यार्थियों की लगन का प्रमाण है। विद्यालय की अंडर-17 वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता हेमबती नाग ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। उन्हें खेल के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि जिले और पूरे बस्तर संभाग के लिए गौरव का क्षण रहा। विद्यालय के प्राचार्य पी.एस. डेनियल ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षिका को बधाई देते हुए कहा कि - यह सफलता हमारे विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है। विद्यालय ऐसी प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन देता रहेगा।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उत्साह के साथ लोग ले रहे हैं लाभ

रायपुर। बिजली बिल के बोझ से मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने हेतु पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने बलौदाबाजार के लोग उत्साहित हैं। अब तक 1700 लोगों ने आवेदन किया है जिसमें से 331 लोगों ने अपने छत पर सोलर पैनल लगवाकर योजना का लाभ लिया है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक किलोवाट सोलर सिस्टम पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार तथा तीन किलोवाट से दस किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 30 हजार रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गत 8 सितम्बर को रायपुर स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम से इसका शुभारंभ कर लाभार्थियों को सब्सिडी राशि का अंतरण किया। योजना को और सुगम बनाने के लिए 20 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान छह से सात प्रतिशत की ब्याज दर पर सोलर लोन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तपोषण संभव है।

गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन से छत्तीसगढ़ को मिलेगा विकास का नया ट्रैक

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार

डबल इंजन सरकार में विकास की पटरी पर दौड़ रहा छत्तीसगढ़ - मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत परियोजनाओं में 2,223 करोड़ लागत की गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है, जो प्रदेश के पश्चिमी अंचल के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार कर रहा है। डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से छत्तीसगढ़ विकास की पटरी पर तेज़ी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, बल्कि इस परियोजना से सम्पूर्ण मध्य भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का रेल नेटवर्क आधुनिकता, गति और जनसुविधा के नए युग में प्रवेश कर चुका है। छत्तीसगढ़ को इस दिशा में जो निरंतर सहयोग मिल रहा है, वह राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विस्तार का सशक्त आधार बनेगा।

उल्लेखनीय है कि 84 किलोमीटर लंबी परियोजना राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) और गोंदिया (महाराष्ट्र) जिलों से होकर गुजरेगी। इसे पांच वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत 15 प्रमुख पुल, 123 लघु पुल, 1 सुरंग, 3 रोड ओवर ब्रिज (ऋद्धक्ष) और 22 रोड अंडर ब्रिज (ऋक्ष) का निर्माण किया जाएगा।

आकांक्षी जिला राजनांदगांव में यह परियोजना न केवल यात्रियों के आवागमन को सुलभ बनाएगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और निवेश को भी नई दिशा देगी। यह रेल मार्ग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेगा और छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूती प्रदान करेगा।

परियोजना पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष लगभग 30.6 मिलियन टन अतिरिक्त माल यातायात संभव होगा। इससे रेलवे की आमदनी में वृद्धि होगी और राज्य की औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल व तैयार उत्पादों के परिवहन में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही अनुमानतः 23 करोड़ किलोग्राम ष्ट्हर उत्सर्जन में कमी, 4.6 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत और लगभग ?514 करोड़ की लॉजिस्टिक लागत में कमी का लाभ मिलेगा, जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह पहल हर वर्ष लगभग 1 करोड़ पेड़ों के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, जो सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई रेल लाइन के माध्यम से रायगढ़ मांड, कोरबा और इब घाटी की खदानों से कोयला परिवहन की गति बढ़ेगी, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के थर्मल पावर प्लांट्स को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे प्रदेश की खनिज अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक तंत्र दोनों को स्थायित्व मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गोंदियाङ्कडोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा, औद्योगिक प्रगति और पर्यावरणीय संतुलन का सशक्त आधार प्रदान करेगी।यह परियोजना छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने और विज़न विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

संतों के आशीर्वाद और जनसहयोग से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है विकास और आस्था के मार्ग पर - मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पुण्यभूमि माता कौशल्या की जन्मस्थली होने के साथ-साथ प्रभु श्रीराम का ननिहाल भी है — यह हमारे लिए परम सौभाग्य और गर्व का विषय है। प्रभु श्रीराम ने अपने चौदह वर्षों के वनवास काल का अधिकांश समय इसी पावन छत्तीसगढ़ की धरती पर व्यतीत किया, जिससे यह भूमि भक्ति, त्याग और मर्यादा की दिव्यता से आलोकित हुई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम बड़े जुंगेरा स्थित माँ कौशल्या धाम, जामड़ी पाटेश्वर आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत श्री रामकृष्णदास महात्यागी एवं संत श्री रामजानकीदास महात्यागी के समाधि स्थल पहुँचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दोनों संत महापुरुषों के राष्ट्र, समाज और अध्यात्म के प्रति योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग, तप और सेवा से छत्तीसगढ़ की यह भूमि आज भी आलोकित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबाजी तेजस्वी साधक और त्याग, सेवा व अध्यात्म के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोककल्याण और मानवता की सेवा को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे संतों की प्रेरणा ही हमारे समाज की आत्मा और राज्य के सांस्कृतिक गौरव की आधारशिला है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान श्रीराम के ननिहाल में आकार ले रहा यह दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रतीक बनेगा। उन्होंने संत बालक दास महात्यागी जी से भेंट कर निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद भोजराज नाग, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

डॉ. एस. के. वर्मा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कृषि विज्ञान केंद्र, मुंगेली को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. के. वर्मा को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 10वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज़ के दौरान प्रदान किया गया, जो 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक एमपीयूएटी, उदयपुर (राजस्थान) में सम्पन्न हुआ।

यह सम्मान मुख्य अतिथि डॉ. अनिल कुमार सिंह, पूर्व कुलपति, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर एवं पूर्व उप महानिदेशक आईसीएआर, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉ. बी. के. चक्रवर्ती, पूर्व निदेशक, बांग्लादेश सरकार, डॉ. यू. एस. शर्मा, पूर्व कुलपति, एमपीयूएटी, उदयपुर, तथा सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार कर्णाटक, कुलपति, एमपीयूएटी, उदयपुर भी उपस्थित रहे। डॉ. वर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद में अपने कार्यकाल के दौरान बंजर भूमि को उत्पादक बनाने हेतु बागवानी विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्य किया। उनके मार्गदर्शन में केंद्र परिसर की अनुपजाऊ भूमि को विकसित कर फलोद्यान एवं नर्सरी प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। आज यह परिसर आम, अमरूद, अनार, बेल, चीकू, सीताफल नींबू, पपीता, कटहल, आँवला, जामुन, इमली आदि फलों के हरित-भरे उद्यान के रूप में विकसित हो चुका है। साथ ही, डॉ. वर्मा द्वारा किसानों को नर्सरी तकनीक, पौध उत्पादन, बागवानी प्रबंधन एवं सतत कृषि पद्धतियों के प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय योगदान दिया गया है। उनके इन प्रयासों से न केवल कृषि विज्ञान केंद्र की पहचान सुदृढ़ हुई है, बल्कि क्षेत्र के किसानों में बागवानी के प्रति नई चेतना और प्रेरणा का संचार हुआ है।

मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत राज्य के 58 हजार शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ किया गया है। इस अंकेक्षण का आयोजन राज्य के सभी 58 हजार शालाओं में 6 से 8 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने प्रदेश के सभी जिला एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सामाजिक अंकेक्षण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह बच्चों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति जानने और उसे सुधारने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुदाय की भागीदारी सक्रिय हो और अंकेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाया जाए। शिक्षा मंत्री श्री यादव ने यह भी कहा कि यह अभियान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी अपेक्षित है।

इस अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घटकों का त्वरित क्रियान्वयन कर बच्चों की सीखने की उपलब्धियों में सुधार लाना है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर शिक्षा की गुणवत्ता पर ठोस प्रभाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

2 अक्टूबर 2025 को आयोजित ग्राम सभा में विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसके बाद प्रत्येक शाला के लिए सामाजिक अंकेक्षण टीमों का गठन किया गया है, जिनमें निकटवर्ती विद्यालय के शिक्षक को टीम लीडर तथा स्थानीय समुदाय से शिक्षा में रुचि रखने वाले सदस्यों को शामिल किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई-हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रश्नावली तैयार करने और प्रशिक्षण देने का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया गया है। समग्र शिक्षा इस कार्यक्रम के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान समुदाय से कुल 20 प्रश्नों पर जानकारी एकत्र की जा रही है। इसमें बच्चों की पठन क्षमता, गणितीय कौशल, शिक्षकों की उपस्थिति, पुस्तकालय उपयोग, परीक्षा परिणाम, स्थानीय भाषा के उपयोग जैसे पहलू शामिल हैं। इसी के साथ समुदाय से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर विद्यालयों की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।

विद्यालयों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की तिथि तय कर समुदाय के सदस्यों को उपस्थिति हेतु आमंत्रित किया गया है। विशेष रूप से, यदि कोई परिवार अपने सगे-संबंधी की स्मृति में न्यौता भोज卐आयोजित करना चाहे तो वह भी इसी दिन किया जा सकता है। जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान समुदाय की उपस्थिति और आयोजित न्यौता भोजों की संख्या को भी आकलन में शामिल किया जाएगा।

अंकेक्षण के बाद भरे गए प्रपत्रों पर समुदाय के हस्ताक्षर लेकर उन्हें विकासखंड स्तर पर जमा किया जाएगा, जहाँ ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर कमजोर प्रदर्शन करने वाली शालाओं की सूची तैयार की जाएगी। इन शालाओं का निरीक्षण जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ताकि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पाई जाएगी, वहाँ समुदाय से इच्छुक प्रतिभागियों की सूची बनाकर उनके सहयोग से सुधार कार्य आरंभ किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की क्षमता वृद्धि तथा बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।

पशुपालन और डेयरी उद्योग से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे: मंत्री रामविचार नेताम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पशुधन विकास मंत्री मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पशुपालन और डेयरी उद्योग के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में भारत की पहचान है। यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

पशुधन विकास मंत्री नेताम पशुधन गणना के लिए भारत सरकार इंटीग्रेटेड सिम्पल सर्वे के लिए तैयार किए गए ई-लिस मोबाईल एप्प एण्ड डाटाबेस पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। राजीव गांधी नेशनल भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंसाधन संस्थान में आयोजित इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में उत्तरी जोनल स्तरीय इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही बिहार, ओड़िसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप के प्रतिनिधियों तथा पशुधन विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

पशुपालन मंत्री श्री नेताम ने कहा कि पशुधन क्षेत्र की संभावनाओं का दोहन करने एवं आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2047 तक के अनुमानित उत्पादन का आंकलन किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में दूध उत्पादन 2124 हजार टन है एवं वृद्धि दर 8.58 प्रतिशत है। वर्ष 2047 तक राज्य का दूध उत्पादन 12209 हजार टन और अण्डा उत्पादन 2023-24 में 23876 लाख से बढ़कर वर्ष 2047 में उत्पादन 112351 लाख होने का अनुमान है इसी प्रकार मांस उत्पादन जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

श्री नेताम ने कहा कि आंकड़ों का उपयोग वैश्विक स्तर पर नियोजन, नीति निर्माण, अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण है जिसमें प्रमुख पशु उत्पादन एवं उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली से आए सांख्यिकीय सलाहकार एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक जगत हजारिका कहा कि भारत सरकार द्वारा पशुधन की गणना के लिए ई-लिस एप्प के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-लिस से प्राप्त गणना सटीक व पारदर्शी परिणाम देते है। ये आकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को दर्शाते हैं।

प्रधान वैज्ञानिक डॉ. प्राची साहू ने भी संबोधित किया। उन्होंने ई-लिस के सभी पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग के संचालक चंद्रकांत वर्मा ने प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी नेशनल भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के अधिकारी महेश सोन कुसरे, अपर संचालक के.के. ध्रुव सहित जिले स्तर के अधिकारी शामिल थे।

दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 7.20 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बालोद जिले की दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 7 करोड़ 20 लाख 13 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं। स्वीकृत कार्यों में विकासखण्ड-गुण्डरदेही की ग्राम पंचायत-कांदुल के अंतर्गत नवीन हाट बाजार के समीप नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 60 लाख 26 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना से निस्तारी, भू-जल संवर्धन, पेयजल आवागमन एवं किसानों द्वारा स्वयं के साधन से 25 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगी।

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, कैम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

बार-बार वैक्स कराना स्किन के लिए हो सकता खतरनाक

लचीलापन होता है कम

कुछ लड़कियां शरीर पर जरा सा बाल आते ही वह जल्दी-जल्दी वैक्सिंग कराने लगती हैं। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि थोड़े अंतराल में बार-बार वैक्सिंग कराते है तो आप अपनी त्वचा का लचीलापन खो देती है। इसकी वजह से त्वचा में जल्द ही झुर्रियों की संभावना ज़बढ़ जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वैक्स स्ट्रिप को कितनी आराम से निकालते है, लेकिन बार-बार ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी त्वचा ढ़ीली होने लगती है।

जलन और लाली

बार-बार वैक्सिंग की वजह से शरीर के आसपास लाल-लाल चकते के निशान बन जाते हैं। हालांकि यह साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप त्वचा संवेदनशील है तो बार-बार वैक्स कराने से आपको जलन की शिकायत हो सकती है। इसलिए आपको इस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। बर्फ से सिंकाई आपकी त्वचा को शांत करने में मदद करती है।

त्वचा पर चकत्ते

वैक्सिंग के बाद आपको खुजली जैसा भी महसूस हो सकता है, और आप त्वचा पर खुजली करते है तो त्वचा पर चकत्ते और लाल दाने जैसे उभरने लगते हैं। अत्यधिक संवेदनशील त्वचा के लिए बिकनी वैक्सिंग कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है। त्वचा पर चकत्ते होने पर स्वीमिंग पूल से बचें।

एलर्जी रिएक्शन

यह समस्या वैक्स प्रोडक्ट से एलर्जी से पीड़ित महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है। संवेदनशील त्वचा के लिए, एलर्जी की प्रतिक्रिया बहुत ही आम होती है। अगर आप इस तरह का कुछ अनुभव करते हैं तो जल्दी से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें।

वैक्सिंग करने से ब्लीडिंग

वैक्सिंग के बाद आपको हल्की ब्लीडिंग जैसी समस्याओं हो सकती है।

> शरीर के अनचाहे बालों का हटाने के लिए वैक्सिंग सबसे सस्ता और सरल साधन है। वैक्सिंग दस से 15 दिनों का अस्थायी उपचार देते हैं। इसलिए वैक्सिंग अनचाहे बालों से लंबे समय तक छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। रेजर या हेयर रिमूवर के इस्तेमाल से कई बार बालों की ग्रोथ जल्दी उग जाती है। इसके लिए वैक्सिंग ही सबसे बेहतर रहती है लेकिन बार-बार बिना अंतराल के वैक्सिग कराने से कई तरह की समस्या हो सकती है जैसे इंफेक्शन और त्वचा पर जलन होना। आइए जानते हैं कि वैक्सिंग से क्या-क्या नुकसान होते हैं।

क्योंकि बार-बार वैक्स करवाने से स्किन संवेदनशील बन जाती है। वैक्स स्ट्रिप खींचने के बाद पोर्स से खून आने लगता है। तुरंत ठंडा सेक लगाने से खून बहाना बंद हो जाता है और बाद में लाल धब्बे में नहीं पड़ते।

तनाव को कह दो बाय बाय

आप सही अर्थों में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखें. कई दफा व्यक्ति की बीमारियां और शारीरिक पीड़ायें मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू से जुड़ी होती हैं. जिस पर सामान्यत: हम ध्यान नहीं देते. उदाहरण के लिए आप फाइब्रोसाइटिस ले सकते हैं. यह ऐसी स्थिति है जिस से मांसपेशियों में दर्द, नींद और मूड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. पुरुषों से कहीं अधिक महिलाओं में यह समस्या दिखती है जो ताउम्र रह सकती है. इस की कई वजह हो सकती हैं. जैसे अर्थराइटिस, संक्रमण या फिर व्यायाम की कमी. जरूरी है कि शरीर के साथ मानसिक सेहत का भी ख्याल रखा जाए. मानसिक बीमारियों की शुरुआत होती है डिप्रेशन से. एक व्यक्ति जब किसी बात को लेकर थोड़े समय के लिए उदास होता है तो उस के खतरनाक नतीजे नहीं होते. मगर जब उदासी लंबे समय तक चलती है तो यह डिप्रेशन में बदल जाती है और व्यक्ति हमेशा उदास, परेशान, तन्हा रहने लगता है. नकारात्मक बातें करता है और दूसरों से मिलने से बचने का प्रयास करता है. इस का असर उस के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है.

दिल्ली जैसे महानगरों में लोग डिप्रेशन के साथसाथ टेंशन के भी शिकार हो रहे हैं. एक तरफ अधिक से अधिक रुपए कमाने की जरूरत तो दूसरी ओर रिश्तों में बढ़ रही खटास और एकाकी जीवन उन के दिमाग में तनाव बढ़ा रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 35ब से ज्यादा लोग एक्सरसाइज करने में आलस करते हैं. शारीरिक रूप से कम सक्रियता व्यक्ति के लिए दिल की बीमारियों, कैंसर, डायबिटीज और हड्डियों के रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों का खतरा भी बढ़ाती है. मानसिक रोगों से बचना है तो कुछ बातों का खयाल रखें।

व्यायाम करें

व्यायाम करने से एंडोर्फिन का संचार बढ़ता है. यह एक ऐसा हार्मोन है जो दर्द और तनाव से लड़ता है और आप को अच्छी नींद लाने में सहायक होता है. हर रोज स्ट्रैचिंग, योगा, वौकिंग, स्विमिंग, डांसिंग जैसे व्यायाम आप के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं.

सामाजिक बनें

अध्ययनों के मुताबिक जिन व्यक्तियों को सामाजिक सहयोग मिलता है वे तनाव, डिप्रेशन और दूसरे मानसिक रोगों से दूर रहते हैं. अपनी समस्याएं दूसरों से डिस्कस करने पर नए रास्ते भी मिलते हैं और तनाव भी घटता है.

पसंदीदा काम करें

अक्सर लोग अपनी हौबी के लिए समय नहीं निकाल पाते जो अनुचित है. अपनी हौबी को अपनाएं. इस से जीवन के प्रति आप का उत्साह बढ़ता है और सोच सकारात्मक होती है. अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाएं. यह कोई भी काम जैसे लेखन, बागवानी, कुकिंग आदि कुछ भी हो सकता है.

फ्रूट फेस पैक से पाएं नैचुरल ग्लो

ब्यूटी पार्लर का कैमिकल्स वाला ट्रीटमैंट केवल बाहरी निखार दे सकता है और कभीकभी यह त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जबकि नैचुरल उपचार त्वचा को अंदर से निखार कर उसे मुलायम और जवां बनाता है. खिलीखिली और नैचुरल ग्लो वाली त्वचा के लिए घर पर फलों से बने ये फेस पैक आजमाएं.

केले से बना पैक

केला ऐंटीऔक्सीडैंट से भरपूर फल है. इस से बना पैक त्वचा की खुश्की दूर कर उसे मुलायम बनाता है. इस का पैक बनाने के लिए 1 पके केले को मसल लें. फिर उस में शहद और औलिव औयल मिला कर चेहरे पर लगाएं. 10 मिनट लगा रहने के बाद चेहरे को धो लें.

पपीते से बना पैक

पपीता ऐंटीऔक्सीडैंट, फ्लावोनौइड्स और मिनरल्स से भरपूर फल है. यह नैचुरल ऐंटीएजिंग है. इस का पैक बनाने के लिए इस का गूदा निकाल कर उस में शहद, नीबू का रस और मुलतानी मिट्टी मिला कर चेहरे पर लगाएं. यह पैक त्वचा को नमी तो देगा ही, साथ ही डैड स्किन हटा कर त्वचा की भीतरी परत को भी स्मूद बनाएगा.

स्ट्राबैरी से बना पैक

इस से बना पैक त्वचा के सूर्य के संपर्क में आने पर हुई परेशानी को दूर करेगा. इस का पैक बनाने के लिए इस का रस निकाल कर उस में योगर्ट मिला कर चेहरे पर लगाएं. यह पैक त्वचा को प्राकृतिक निखार देता है.

तरबूज से बना पैक

तरबूज पानी से भरपूर फल होने के कारण त्वचा को अंदरूनी नमी दे उस की खुश्की दूर करता है. इस का पैक बनाने के लिए इस का रस निकाल कर इस में योगर्ट और मिल्क पाउडर मिला कर चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट लगाए रखने के बाद चेहरे को धो लें.

संतरे से बना पैक

संतरा विटामिन सी से भरपूर होने के कारण त्वचा को हाइड्रेट करता है, साथ ही त्वचा को गहराई तक साफभी करता है. इस का पैक बनाने के लिए इस का रस निकाल कर उस में योगर्ट और गुलाबजल मिला कर चेहरे पर लगा कर 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें.

बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा, ऐसे रखें दिल का ख्याल

वो दौर गया जब सिर्फ 50 साल की उम्र के ही लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होता था. आज की बदलती जीवनशैली के चलते अब 30 के उम्र के लोग भी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आने लगे हैं. जी हां, 30 से 40 उम्र के लोगों को दिल संबंधी बीमारियां होने लगी है. इन रोगों का कारण सिर्फ तनाव है और इससे मुक्ति पाने के लिए ये लोग धूम्रपान, नींद की दवाएं, शराब का सेवन करते हैं. जो उन्हें दिल की बीमारी की तरफ ले जा रही है. आपको ये बीमारी ना हो और आप इससे खुद को बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहें, इसीलिए हम आपको दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण बता रहे हैं जिन्हें समय से पहले जानकर गंभीर दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है.

ये हैं लक्षण

छाती में बेचैनी महसूस होना: यदि आपकी आर्टरी ब्लौक है या फिर हार्ट अटैक है तो आपको छाती में दबाव महसूस होगा और दर्द के साथ ही खिंचाव महसूस होगा.

मतली, हार्टबर्न और पेट में दर्द होना: दिल संबंधी कोई भी गंभीर समस्या होने से पहले कुछ लोगों को मितली आना, सीने में जलन, पेट में दर्द होना या फिर पाचन संबंधी दिक्कतें आने लगती हैं.

हाथ में दर्द होना: कई बार दिल के रोगी को छाती और बाएं कंधे में दर्द की शिकायत होने लगती है. ये दर्द धीरे-धीरे हाथों की तरफ नीचे की ओर जाने लगता है.

कई दिनों तक कफ होना: यदि आपको काफी दिनों से खांसी-जुकाम हो रहा है और थूक सफेद या गुलाबी रंग का हो रहा है तो ये हार्ट फेल का एक लक्षण है.

सांस लेने में दिक्कतें होना: सांस लेने में दिक्कतें होना या फिर कम सांस आना हार्ट फेल होने का बड़ा लक्षण है.

पसीना आना: सामान्य से अधिक पसीना आना खासतौर पर तब जब आप कोई शारीरिक क्रिया नहीं कर रहे तो ये आपके लिए एक चेतावनी हो सकती है.

पैरों में सूजन: पैरों, टखनों, तलवों और एंकल्स में सूजन आने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके दिल में रक्त का संचार ठीक से नहीं हो रहा है.

चक्कर आना या सिर घूमना: कई बार चक्कर आने, सिर घूमने, बेहोश होने, बहुत थकान होने जैसे लक्षण भी एक चेतावनी हैं.

सीलिंग दे मनचाही फीलिंग

सीलिंग की डिजाइन और रंगों को ले कर हर कोई दुविधा में रहता है कि यह कैसी बनवाई जाए. अगर बहुत से विकल्पों वाली सीलिंग डिजाइनें आप को दुविधा में डाल देती हैं, तो इस की वजह जानकारी की कमी और सब से अच्छी सीलिंग पाने की इच्छा होती है.

सीलिंग की डिजाइनों का वर्गीकरण कोई नहीं कर सकता. वजह रोज नई डिजाइनें बाजार में आती हैं, जो पहले वाली से कहीं बेहतर नजर आती हैं. लेकिन सीलिंग निहायत ही व्यक्तिगत पसंद का मामला है, जो एक हद तक आप की रुचि भी प्रदर्शित करता है. पहले राजमहलों और फिर फिल्म उद्योग जगत की शान मानी जाने वाली फौल्स सीलिंग आज हर किसी की पहुंच में है, जिस में नया तड़का अब लाइट का लग गया है. कहने का मतलब यह नहीं कि पीओपी (प्लास्टर औफ पैरिस) का जमाना अब लद गया है, बल्कि बदलाव यह आया है कि रंगबिरंगी लाइटें सीलिंग का जरूरी हिस्सा बन गई हैं, जिन से खुबसूरती में चारचांद लग जाते हैं. जब भी सीलिंग कराएं तब केवल अपने दिल की सुनें. उस डिजाइन को छत पर साकार करवाएं जो मुद्दत से आप के जेहन में हो. आइए जानें सीलिंग के बारे में:

ट्रैडिशनल डिजाइन

यह ठीक है कि एकदम सादगी वाली सीलिंग कोई नहीं चाहता, इसलिए अब हलकी डिजाइनों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं. भोपाल के नामी शोरूम झूमरवाला के नवीन साहू का कहना है कि हलकी पीली और औफव्हाइट सीलिंग का दौर दोबारा लौट रहा है. हां, इन में लाइट जरूर लोग नईनई डिजाइन वाली लगवा रहे हैं. अब इलैक्ट्रिक आइटम की वैराइटी और रेंज काफी बढ़ गई है.

अगर ड्राइंगरूम की सीलिंग प्लेन या हलके रंग की है तो उस में तरहतरह की लाइटें लगवाई जा सकती हैं. आमतौर पर सैंटर में एक बड़ा लैंप या झूमर ठीक रहता है और चारों कोनों पर एलईडी बल्ब कमरे को बेहतर लुक देते हैं. कमरे के आकार के अनुपात में बल्बों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

नैचुरल डिजाइन

जब फौल्स सीलिंग चलन में नहीं आई थी तब कमरों और दीवारों को नैचुरल सीनरीज वाले पोस्टरों से ही सजाया जाता था. मसलन झरने का दृश्य, नीला आसमान, छोटेछोटे खिले हुए फूल आदि.

ग्लोइंग स्किन के लिए ब्यूटी केयर रूटीन में शामिल करें ये तरीके

ऋतु की फिजिक तो परफैक्ट थी, लेकिन स्किन उतनी चार्मिंग नहीं थी. वह सोचती मैं मार्केट में आने वाला हर महंगा प्रोडक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूं, फिर भी मेरी स्किन यंग व ग्लोइंग क्यों नहीं दिखती. फिर जब उस ने इस बारे में अपनी फ्रैंड शिखा से बात की तो उस ने बताया कि अकसर हम स्किन की खूबसूरती को सिर्फमहंगी क्रीम्स के इस्तेमाल से जोड़ते हैं, जबकि स्किन खूबसूरत बनती है रोज उस की देखभाल करने से. अगर आप भी अपनी स्किन को आकर्षक बनाना चाहती हैं तो इन टिप्स पर गौर फरमाएं:

स्किन टाइप व क्लींजिंग

विज्ञापन देख कर स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने का क्रेज महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, जबकि इन्हें खरीदने से पहले हमें अपनी स्किन टाइप पर गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना स्किन टाइप जाने प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से सही रिजल्ट नहीं मिल पाता. इसलिए स्किन टाइप जानना जरूरी है. अगर आप की स्किन रफहै तो इस का मतलब आप की स्किन ड्राई है और ऐसी स्किन पर खुशबू वाले क्लींजर का भूल कर भी इस्तेमाल न करें. सौफ्ट क्लींजर ही प्रयोग करें. वहीं औयली स्किन में बड़ेबड़े रोमछिद्रों के साथसाथ त्वचा पर औयल भी नजर आता है. इस के लिए औयलफ्री फेस वाश प्रयोग करें. सैंसिटिव स्किन की प्रौब्लम यह होती है कि कुछ भी ट्राई करने पर जलन व रैडनैस नजर आने लगती है. इस के लिए माइल्ड क्लींजर यूज करने करें व त्वचा को टौवेल से न रगड़ें वरना स्किन रैड हो सकती है. नौर्मल स्किन क्लीयर होती है, जिस पर आमतौर पर हर तरह का ब्रैंडेड प्रोडक्ट ट्राई किया जा सकता है. यानी क्लींजिंग के प्रयोग से पसीना, औयल व गंदगी को दूर किया जा सकता है.

टोनिंग

कभीकभी क्लींजिंग के बाद भी स्किन में थोड़ीबहुत गंदगी रह जाती है, जिसे टोनर की मदद से दूर किया जा सकता है. इस के लिए कौटन बौल को टोनर में डुबो कर फेस पर लगाएं. यह ऐक्स्ट्रा क्लींजिंग इफैक्ट आप की स्किन में मौइश्चर बनाए रखने का काम करता है. इसलिए क्लींजिंग के बाद टोनिंग करना न भूलें.

ऐक्सफौलिऐशन से करें डैड सैल्स रिमूव

रोजाना लाखों स्किन सैल्स बनते हैं, लेकिन कभीकभी ये सैल्स त्वचा की परत पर बन जाते हैं जिन्हें हटाने की जरूरत पड़ती है. ऐक्सफौलिएट प्रक्रिया से डैड स्किन सैल्स को रिमूव किया जा सकता है. इस से ऐक्ने, ब्लैकहैड्स की परेशानी से भी छुटकारा मिलता है. इस के बैस्ट रिजल्ट के लिए इस प्रक्रिया को टोनिंग के बाद और मौइश्चराइजिंग से पहले करना चाहिए.

पौष्टिक भोजन व पर्याप्त नींद

आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, दालें व सब्जियां ज्यादा से ज्यादा शामिल करें. चिकन, अंडे, मछली आदि का भी सेवन करें. पूरी नींद ले कर डल स्किन, डार्क सर्कल्स जैसी परेशानियों से छुटकारा पाएं. इस तरह डेली अपनी स्किन की केयर कर खुद को और खूबसूरत बना पाएंगी.

सामंथा रुथ प्रभु के फोन वॉलपेपर पर किसकी तस्वीर, लेट्स टॉक सेशन में एक्ट्रेस ने खोले राज

साउथ की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का फिल्मी करियर हिट रहा है और फैंस ने भी एक्ट्रेस पर खुलकर प्यार लुटाया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। तलाक के बाद सबसे ज्यादा एक्ट्रेस को हेल्थ प्रॉब्लम हुई और उन्हें अपनी ऑटोइम्यून मायोसिटिस नाम की बीमारी के बारे में पता चला। बीमारी के बारे में जानने के बाद से ही एक्ट्रेस ने अपनी हेल्थ पर फोकस करना शुरू किया और अब वो कुछ दिन खुद को हील करने में लगाती हैं। सामंथा रुथ प्रभु ने मौन की तरफ लौटने का फैसला लिया है और फैंस से इस बारे में बात की है। एक्ट्रेस हर तीन महीने में एक बार ईशा फाउंडेशन जाती हैं और शारीरिक और मानसिक शांति के लिए सेशन लेती हैं।

वहां जाने से पहले उन्होंने फैंस से बात की और उनके पूछे हुए सवालों का जवाब दिया। एक यूजर ने सामंथा से सवाल किया कि वो आगे किस प्रोजेक्ट में दिखने वाली हैं। इस सवाल का खुलकर जवाब न देते हुए एक्ट्रेस ने मुस्कुराकर कहा कि वो कई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं ले सकती।

मेरे लिए फैशन वह है जो आरामदायक हो- दिव्यांका

मुंबई में इन दिनों बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2025 चल रहा है। इसमें बॉलीवुड और टीवी की कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। यहां लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी दहिया भी दिखाई दीं। उन्होंने आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में फैशन और ब्रांड्स पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान अभिनेत्री ने बताया कि उनके लिए फैशन का क्या मतलब है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ब्रैंड के प्रति ज्यादा लगाव रखती हैं, तो दिव्यंका ने कहा, नहीं, मैं ब्रैंड पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैं अपनी पसंद की चीजें लेना पसंद करती हूं, चाहे उनका ब्रांड कुछ भी हो। अगर वह मुझे पसंद आती है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण है। जो मुझे सूट करता है और जो मुझे पसंद है, मैं वही चुनती हूं, चाहे उसका ब्रांड कुछ भी हो।

उनके लिए फैशन के क्या मायने हैं, इस बारे में आगे बात करते हुए दिव्यंका ने आईएएनएस को बताया, मेरे लिए फैशन वह सब कुछ है जो आरामदायक हो। हां, यह आंखों को भाने वाला होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह मेरे लिए आरामदायक होना चाहिए। जो भी चीज आरामदायक होने के साथ-साथ आकर्षक भी हो, वह फैशन है, चाहे वह सादा हो या शानदार।

दिव्यांका त्रिपाठी अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारतीय परिधानों में दिखाई देती हैं। उनके फैशन सेंस का लोग जमकर तारीफ करते हैं। वह पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के परिधानों को अच्छी तरह से कैरी करती दिखाई देती हैं।

दिव्यांका को टीवी सीरियल बनू मैं तेरी दुल्हन से प्रसिद्धि मिली। इसके बाद वो सीरियल ये है मोहब्बतें में डॉ. इशिता भल्ला की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में बस गईं। यह भारतीय टीवी सीरियल्स के लोकप्रिय पात्रों में से एक है। फैंस उन्हें प्यार से 'इशिमा' भी कहते हैं, जो शो में उनकी ऑनस्क्रीन बेटी उन्हें कहकर बुलाती है।

दिव्यांका ने 2016 में अभिनेता विवेक दहिया से शादी की। यह कपल अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को फिटनेस और कपल गोल्स की प्रेरणा देता दिखाई देता है। यह कपल टीवी जगत की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है।

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल जी के सम्मान में सभी नगरीय निकायों में बना रहे अटल परिसर - अरुण साव

अरूण साव ने 3.16 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण, 2.49 करोड़ की लागत के एसटीपी का भूमिपूजन भी किया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज जांजगीर-चांपा जिले के चार नगरीय निकायों में तीन करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल परिसरों तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ में दो करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एसटीपी का भूमिपूजन भी किया। श्री साव ने पामगढ़ नगर पंचायत पामगढ़ में 19 लाख 95 हजार रुपए, राहौद नगर पंचायत के बुंदेला चौक में 19 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत में 19 लाख 93 हजार रुपए एवं नवागढ़ नगर पंचायत के हाट-बाजार परिसर में 19 लाख 95 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। विधायक ब्यास कश्यप तथा पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पामगढ़ नगर पंचायत में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने राहौद नगर पंचायत के लिए दो करोड़ रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए तीन करोड़ रुपए तथा नवागढ़ नगर पंचायत के लिए ढाई करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री साव ने नगर पंचायत राहौद के वार्ड क्रमांक 8 में सांस्कृतिक भवन लागत 11 लाख रुपए, देवांगन समाज धर्मशाला में अतिरिक्त कक्ष लागत 10 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक 15 में सामुदायिक भवन लागत 15 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक 10 में पकरिया पारा में स्कूल के पास सांस्कृतिक भवन लागत 10.42 लाख रुपए, नगर पंचायत खरौद में सी.सी. रोड निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 06 व 13 के पांच विभिन्न मार्गों पर 22.45 लाख रुपए की लागत से पूर्ण, वार्ड क्रमांक 13 में पुलिया से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य लागत 27.41 लाख रुपए, शबरी देवी शिक्षा समिति भवन निर्माण कार्य लागत 9.99 लाख रुपए एवं वार्ड क्रमांक 07 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 9.83 लाख रुपए, गांधी चौक, मुक्तिधाम, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, शीतला मंदिर एवं कंपाटनी मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक कार्य लागत 95.84 लाख रुपए एवं नवागढ़ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में सांस्कृतिक भवन निर्माण लागत 24.57 लाख रुपए का भी लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। उनके सम्मान में राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। अटलजी ने गांवों, किसानों और नागरिकों के लिए ऐतिहासिक योजनाएं शुरू कीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव तक पहुंच और विकास संभव हो पाया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ग्रामीण विकास और किसानों को शून्य ब्याज पर ऋण संभव हुआ। उन्होंने ही छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की नींव रखी। आज छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है, तो उसका श्रेय अटलजी की दूरदृष्टि को जाता है। अटल परिसर उनकी राष्ट्र सेवा, विकास के प्रति दृष्टिकोण और आदर्श मूल्यों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

श्री साव ने कहा कि यह परिसर केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला केंद्र बनेगा। हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने का काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वादा पूरा कर रही है, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रही है।

विधायक ब्यास कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि अटलजी छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निर्माता हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की वर्षों पुरानी आकांक्षा को समझा और उसे साकार कर एक नया इतिहास रचा। आज हम उनके आदर्शों और योगदान को स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा एवं परिसर का लोकार्पण कर रहे हैं। यह वास्तव में अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक क्षण है। उन्होंने कहा कि अटलजी न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्रनायक भी थे, जिनके विचार और आदर्श आज भी हमें दिशा देते हैं। उनकी प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ियाँ उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेंगी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल ने कहा कि आज जिले के चार नगरीय निकायो में अटलजी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। यह केवल प्रतिमा का अनावरण नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा और अस्मिता को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि अटलजी ने न केवल छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं को समझा, बल्कि उसे साकार भी किया। वर्षों से हमारे पुरखे यह सपना देखते आ रहे थे कि हमारा छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, पर उसे पूरा करने का ऐतिहासिक कार्य अटलजी ने किया।

पूर्व संसदीय सचिव अंबेश जांगड़े, पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी, नगर पंचायत पामगढ़ अध्यक्ष गौरी जांगड़े, नगर पंचायत राहौद अध्यक्ष प्रतिभा कश्यप, नगर पंचायत खरौद अध्यक्ष गोविंद यादव, नगर पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष अर्चना देवांगन और कलेक्टर जन्मेजय महोबे सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

जल जीवन मिशन में कार्य पूर्णता में रायपुर दूसरे स्थान पर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। हर घर नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में कार्य पूर्णता के मामले में रायपुर जिला धमतरी के बाद राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहां 95 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। रायपुर जिले में मिशन के अंतर्गत शामिल 477 गांवों में से 247 में काम पूर्ण कर जल आपूर्ति प्रारंभ की जा चुकी है। इन गांवों में नल जल योजनाओं को संचालन और संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। अब वहां ग्राम पंचायतें पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था का संचालन व संधारण कर रही हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, रायपुर के कार्यपालन अभियंता श्री अनिल कुमार बच्चन ने बताया कि मार्च-2026 तक रायपुर जिले के 126 और गांवों में सभी कार्यों को पूर्ण कर हर घर नल से जल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन में रायपुर जिले के सभी 477 गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कुल 393 पानी टंकिया बनाई जाएंगी जिनमें से 377 का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा शेष 16 पानी टंकियां निर्माणाधीन हैं।

श्री बच्चन ने बताया कि रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाएं बनाने तथा स्वीकृति का कार्य वर्ष 2020-21 में प्रारंभ हुआ था। अलग-अलग चरणों में अलग-अलग गांवों के लिए

योजना बनाकर इसका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि सभी गांवों में कार्यों के निविदाएं ऑनलाइन आंमत्रित की गई हैं तथा नियमानुसार सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर कार्यादेश जारी किए गए हैं। निविदा आमंत्रित कर ही ठेकेदारों को कार्य दिए गए हैं। कार्य पूर्णता के बिना किसी भी निर्माण एजेन्सी को एनओसी जारी नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि धरसीवा विकासखंड के ग्राम नक्टी में नल जल योजना का कार्य पूर्ण कर 11 सितम्बर 2024 को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा वहां नल जल योजना का संचालन एवं संधारण किया जा रहा है।

राज्यपाल ने कोरिया में पीनट बटर हनी फ्लेवर्ड उत्पाद का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कोरिया जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया पीनट बटर-हनी फ्लेवर्ड उत्पाद का शुभारंभ किया। राज्यपाल डेका ने उत्पाद की गुणवत्ता, स्वाद और पैकेजिंग की सराहना करते हुए कहा कि यह उत्पाद कोरिया जिले की सृजनात्मक सोच और कृषि नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। शक्कर की जगह शहद का उपयोग इस पीनट बटर को और भी पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक बनाता है।

राज्यपाल ने कहा कि पिछले कोरिया प्रवास के दौरान उन्होंने सोनहनी शहद उत्पाद का भी शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि यह दूसरा उत्पाद सोनहनी की तरह ही किसानों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि इस पहल से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा और स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि प्रोटीन वर्ल्ड की इस दुनिया में कोरिया का 'पीनट बटर' एक नायाब शुरुआत है। यह उत्पाद न केवल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बल्कि 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को भी सशक्त करता है।

राज्यपाल ने पेंड्रा में कदम्ब के पौधे का रोपण किया

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने गौरेला-मरवाही-पेंड्रा जिला प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मां स्वर्गीय चंपावती डेका के नाम पर कदम्ब पौधा का रोपण किया।

राज्यपाल डेका के हाथों कोरिया में हुआ सम्भाग के पहले स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कोरिया जिले के प्रवास के दौरान बैकुंठपुर स्थित शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सम्भाग के पहले स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण किया। यह अत्याधुनिक लैब भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर समर्पित किया गया है। डीएमएफ मद के सहयोग से स्थापित यह प्रयोगशाला विद्यार्थियों में अंतरिक्ष, भौतिकी, भूगोल और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विद्यालय की छात्राओं से लैब के

तकनीकी पक्षों के बारे में जानकारी ली। कक्षा नवमीं की छात्रा अनुजा ने ऐरोहब मॉडल का प्रदर्शन किया, वहीं कक्षा बारहवीं की उन्नति ने वर्चुअल रियलिटी के उपयोग को समझाया। अन्य छात्राओं ने भी अंतरिक्ष से संबंधित उपकरणों और मॉडलों के कार्यों का जीवंत प्रदर्शन किया। राज्यपाल डेका ने छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान से होने वाले लाभ और उसके प्रभाव से कोई इंकार नहीं कर सकता। यह लैब न केवल अंतरिक्ष विज्ञान बल्कि अन्य विज्ञान विषयों में भी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। पहल की प्रशंसा करते हुए जिला प्रशासन को बधाई दी और उन्होंने लैब के लिए ड्रोन, स्मार्ट बोर्ड एवं प्रोजेक्टर उपलब्ध कराने की सहमति दी।

दमउदहराः प्रकृति, आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सक्ती-कोरबा मार्ग पर, सक्ती से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित दमउदहरा (दमाऊधारा) न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम स्थल है, बल्कि यह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ तक सड़क मार्ग से निजी वाहन या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन सक्ति, जबकि निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है।

दमउदहरा का प्रमुख आकर्षण इसका सुंदर जलप्रपात है, जो ऊँची पहाड़ियों से झरझर गिरते हुए नीचे बहता है। बरसात के मौसम में यह झरना अपने पूरे सौंदर्य पर होता है। चारों ओर फैली हरियाली, झरने की गूंजती ध्वनि और शीतल वातावरण

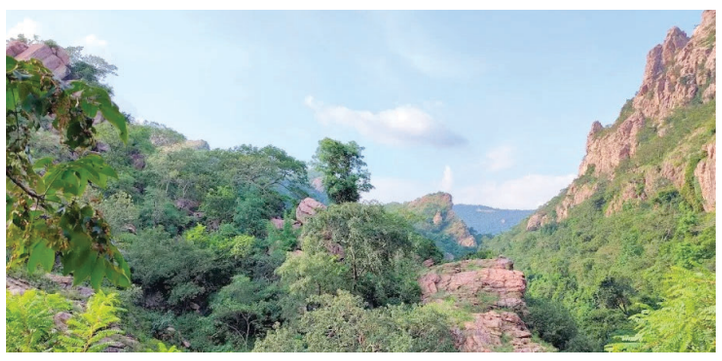

पर्यटकों को मोह लेता है। आसपास के घने जंगल, प्राकृतिक गुफाएँ और ऊँची पहाड़ियाँ इस स्थल को रोमांच और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान बना देती हैं।

धार्मिक दृष्टि से दमउदहरा अत्यंत पूजनीय है। यहाँ राम-जानकी मंदिर, राधा-कृष्ण मंदिर, ऋषभदेव जैन तीर्थंकर का मंदिर, हनुमान मंदिर, भगवान शिव-पार्वती मंदिर और विष्णु-लक्ष्मी मंदिर जैसे कई पवित्र स्थल स्थित हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम अपने वनवास काल में दमउदहरा (गूंजी क्षेत्र) पधारे थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ विश्राम और पूजा-अर्चना की थी, जिससे यह क्षेत्र ऋषभ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इतिहासकार लोचन प्रसाद पांडेय द्वारा खोजे गए 'गूंजी शिलालेख' का उल्लेख भी इस स्थल के महत्व को और बढ़ाता है। इस शिलालेख में उस समय की धार्मिक गतिविधियों, सामाजिक संरचना और स्थानीय शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है, जो दमउदहरा क्षेत्र की प्राचीनता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रमाण है। हर वर्ष जनवरी महीने में यहाँ भव्य मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर-दूर से श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान और पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है। इस समय घाटी में साधु-संतों का संगम होता है। एक रोचक दृश्य यह भी देखा जाता है कि सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही जंगली बंदर घाटी में उतर आते हैं, जो यहाँ की अनूठी प्राकृतिक घटना बन चुकी है।

दमउदहरा पिकनिक और पारिवारिक भ्रमण के लिए भी लोकप्रिय है। लोग यहाँ झरने के पास बैठकर, हरियाली के बीच विश्राम और मनोरंजन का आनंद लेते हैं। मानसून के दौरान झरने में स्नान का अनुभव अविस्मरणीय होता है।

प्रकृति, आस्था, इतिहास और रोमांच का यह संगम दमउदहरा को छत्तीसगढ़ का एक विशिष्ट पर्यटन स्थल बनाता है। यह न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था के विकास में भी इसकी अहम भूमिका है। यहाँ की आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य हर आगंतुक को एक गहरे, आत्मिक अनुभव से भर देता है।

आदि कर्मयोगी शिविर में मेघनाथ को मिली राहत

रायपुर। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिले के जनजातीय बाहुल्य गांव में आदि सेवा पर्व के दौरान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों की मांगों एवं समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त हुये और कई आवेदनों का त्वरित निराकरण भी किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में आयोजित शिविर में कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि के समक्ष मेघनाथ बघेल ने पेंशन की राशि खाते में जमा नहीं होने की जानकारी दी थी। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को मामले की जांच कर राशि दिलाने हेतु निर्देशित किया था।

खास खबर

मोटरसायकलों की आमने-सामने टक्कर, सीआरपीएफ जवान समेत दो की मौत

कोरबा। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे बरपाली मुख्य मार्ग पर दो मोटरसायकलों के बीच हुई भिड़ंत में सीआरपीएफ जवान समेत दो युवकों की मौत हो गई,वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचवाया। मिली जानकारी के अनुसार उरगा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे बरपाली मुख्य मार्ग पर एक बाइक चालक विपरित दिशा में गाड़ी चला रहा था इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाईक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाईकों के परखच्चे उड़ गये और मौके पर ही एक बाइक में सवार सीआरपीएफ जवान पुष्पेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार मोती सागर निवासी दीपक रोहिदास को गंभीर चोटें आई जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई वहीं, दीपक के साथ गाड़ी में बैठे भूषण रोहिदास को भी गंभीर चोट पहुंची जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

बलौदाबाजार। जिले की थाना भाटापारा शहर पुलिस ने समाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर अपने पास चाकू रखकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है तथा चाकू बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में आमजनों की शिकायत एवं समस्याओं को त्वरित निराकरण करने हेतु जिले में महत्वाकांक्षी योजना समाधान सेल प्रारंभ किया गया है, जिसकी सहायता से किसी प्रकार की भी सूचना, शिकायत अथवा अपराधिक गतिविधि की जानकारी समाधान सेल हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 में व्हाट्सएप अथवा कॉल के जरिए प्रदान की जा सकती है। समाधान सेल के माध्यम से आपराधिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड में भी लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 06.10.2025 को समाधान सेल में सूचना मिला की एक आरोपी मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा में चाकू लेकर घूमता है तथा अपने पास चाकू छुपाकर भी रखता है।

अवैध शराब बेचने वाला पकड़ाया

बिलासपुर। जिले की चौकी बेलगहना थाना कोटा पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा उसके कब्जे से अंग्रेजी एवं देशी शराब जब्त किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06.10.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बेलगहना में हिमांशु गुप्ता अपने घर के बगल मे टिन शेड के निचे जमीन मे छुपाकर अंग्रेजी व देशी शराब बिक्री करने हेतु रखा है टीम गठित कर ग्राम बेलगहना में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी हिमांशु गुप्ता के कब्जे से 29 पाव जम्मू अंग्रेजी शराब, 24 पाव गोवा अंग्रेजी शराब, 24 पाव देशी शराब, 04 पाव वाइट चीफअंग्रेजी शराब, 07 पाव मूड ऑफ़ अंग्रेजी शराब, कुल 15.840 बल्क लीटर शराब कुल कीमती 10280 रू को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपी को विधिवत गिरफ्तार क़र न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

बैन कफ-सिरप बेचेने वाले 4 आरोपियों को 10 साल कैद

ड्रग बेचने के दूसरे मामले में कोर्ट ने एक को सुनाई 6 साल की सजा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नशीली टैबलेट और प्रतिबंधित कफसिरप बेचने के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2-2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

वहीं, हेरोइन बेचने के आरोप में एक आरोपी को 6 साल कैद और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि मामला वर्ष 2022 और 2023 का है।

10 सितंबर 2022 की दोपहर 12.15 बजे राजेन्द्र नगर पुलिस ने सावन पुली (20) निवासी कांशीराम नगर और देवनारायण साहू (20) निवासी मौदहापारा को महावीर नगर के पास संदिग्ध हालत में घूमते हुए पकड़ा था। तलाशी में उनके पास से 336 नग नशीली टैबलेट बरामद की गई थी। दोनों इन्हें बेचने की फिराक में थे।

इसी तरह 3 दिसंबर 2022 को मठपुरैना निवासी मोहम्मद असीम (30) और अनिरुद्ध कामड़े (25) को संतोषी नगर के पास पुलिस ने पकड़ा था। तलाशी में उनके पास से 144 नग प्रतिबंधित कफसिरप बरामद किया गया था। वे भी इन्हें अवैध रूप से बेचने जा रहे थे।

सोनडोंगरी निवासी निशांत सिंह संधू (24) को कबीर नगर पुलिस ने 24 सितंबर 2023 को यदुवंशी चौक के पास पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 15.10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपी हेरोइन बेचने की फिराक में घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस की विशेष गश्त दल ने उसे गिरफ्तार किया था।

बिजली विभाग की लापरवाही से दो मवेशियों की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलाईगढ़। जिले के रायकोना गांव में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। गांव में ट्रांसफार्मर से जुड़े खुले तारों में करंट फैल जाने से दो मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत बिजली विभाग से की, लेकिन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के पास खुले तार लटक रहे हैं, जिनमें लगातार करंट दौड़ता रहता है। यह स्थिति ग्रामवासियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं करता, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

इसके साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव का एक और ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब पड़ा है, जिससे उन्हें बिजली की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतें करने के बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की लापरवाही से मवेशियों की जान गई है, और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों की मांग है कि बिजली विभाग तत्काल खुले तारों को दुरुस्त करे और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

सूने मकान में चोरी करने वाले तीन नाबालिग गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बलौदाबाजार। जिले की थाना भाटापारा शहर पुलिस ने के.के. वार्ड भाटापारा स्थित एक मकान में चोरी करने वाले 3 नाबालिग बालकों को हिरासत में लिया है तथा उनसे 10,64,400 कीमत मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 19,372 बरामद किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 04.10.2025 के रात्रि 8.30 बजे से दिनांक 05.10.2025 के प्रात: 6 के मध्य प्रार्थी राजेंद्र कुमार दुबे निवासी के.के.वार्ड भाटापारा के मकान में अज्ञात आरोपियों द्वारा दीवाल फांदकर, घर के चैनल गेट एवं दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर, घर के कमरा अंदर दीवान में गद्दे के नीचे रखे अलमारी के चाबी से अलमारी को खोलते हुए उसमें लगे लाकर को तोड़ दिया गया तथा अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात व नगदी रकम 1,50,000 को चोरी कर लिया गया। रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में धारा 305(क),331(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में भाटापारा शहर पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ ही प्रार्थी के निवास एवं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का भी गहन अवलोकन किया गया, जिसमें 03 संदिग्ध घटनास्थल के आसपास दिखे, जिनकी पहचान करते हुए पुलिस द्वारा 03 नाबालिग बालकों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थी के घर में चोरी करते हुए घर के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपियों द्वारा चोरी के समस्त सामान को श्रीराम कॉलोनी के पास खाली खेत के झाड़ी में छुपा दिया गया था जिससे विधिवत तलाशी अभियान चलाते हुए बरामद किया गया है। कि प्रकरण में आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात कीमती 10,64,400 एवं नगदी रकम 19,372 कुल 10,83,772 का चोरी का सामान बरामद किया गया है। प्रकरण में तीनों अपचारी बालकों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

गांजा तस्करी पर कबीरधाम पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही

श्रीकंचनपथ न्यूज

कवर्धा। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय रायपुर से प्राप्त सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए कबीरधाम पुलिस ने महासमुंद पुलिस से समन्वय करते हुए संयुक्त अभियान में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। थाना बोड़ला अंतर्गत चेकिंग स्विफ्ट डिजायर कार (फर्जी ष्टत्र पासिंग नंबरयुक्त) को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चैम्बर से 57 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

आरोपी मोहसिन खान, निवासी भोपाल, जो उड़ीसा से गांजा लेकर भोपाल जा रहा था, के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा के तहत अपराध दर्ज कर मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत 14 लाख 45 हजार रुपये तथा प्रयुक्त वाहन की कीमत लगभग 5 लाख रुपये है। कुल जप्ती मूल्य 19 लाख 45 हजार रुपये है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक रूपक शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई। साथ ही साइबर सेल कबीरधाम की टीम का भी विशेष योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की नशे की गतिविधि, अवैध तस्करी या समाज को दूषित करने वाले तत्वों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम किया जा रहा है। ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की विशेष टीमें लगातार सक्रिय हैं और ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी। कबीरधाम पुलिस का यह अभियान नशे के व्यापारियों के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि जिले की सीमाओं में अब कोई भी अवैध गतिविधि नहीं चल पाएगी। पुलिस हर स्तर पर निगरानी रख रही है और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को नशा तस्करी, अवैध परिवहन या ऐसे किसी संदेहास्पद कार्य की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें।

झोलाछाप डॉक्टर के इलाज ने ली मासूम की जान, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

बिलासपुर। मध्यप्रदेश में कफसिरप से बच्चों की मौत की खबर के बाद अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिले के सरगांव थाना क्षेत्र के धरदई गांव में एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत कथित तौर पर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के चलते हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी और अंतत: उसकी जान चली गई।मृतक बच्चे की पहचान युग यादव के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। बताया जा रहा है कि युग हाल ही में अपनी नानी के घर मनेन्द्रगढ़ गया था, जहां उसे बुखार और सर्दी की शिकायत हुई। परिजनों के अनुसार, वहां के स्थानीय लोगों ने उसे एक अयोग्य (झोलाछाप) डॉक्टर को दिखाया, जिसने बच्चे को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद युग की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो परिजन उसे मनेन्द्रगढ़ से सरगांव और फिर सोमवार सुबह बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के कारणों की पुष्टि हो सके।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रिसाली

स.क.वि./2024-25/366 (सम्पत्तिकर विभाग) दिनांक 30.09.2025

// स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना //

इस इंश्तहार द्वारा हित रखने वाले हितग्राही हो एहद द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 में स्वत्वाधिकार के अंतरण के संबंध में निम्नलिखित हस्तांतरिती के नाम से जिसका की नगर पालिक निगम रिसाली के सम्पत्तिकर अभिलेख में हस्तांतरणकर्ता के स्थान पर नाम दर्ज किया जाना है। यदि किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है बाद में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	हस्तांतरणकर्ता का नाम	हस्तांतरिती का नाम	हस्तां. का स्वरूप	सम्पत्ति की स्थिति
1.	श्री विजय कुमार सिंह/पिता-स्व. सोमेश्वर सिंह, पता-2ए, सड़क 4, सेक्टर 4, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्री जितेन्द्र कुमार/पिता-हिरऊ राम पता-3/बी, स्ट्रीट 23, सेक्टर 8 भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	बिक्रीनामा	तालपुरी (वार्ड नं. 63, रूआबांधा बस्ती, वार्ड के रूआबांधा बस्ती/तालाब के पीछे छ.ग. गृह निर्माण मंडल आवासीय योजना, मोगरा (एल.आई.जी.) भवन क्रं. 38, कम्पोजिट हाऊस स्कीम एट ट्विनसिटी तालपुरी, ख.नं. 4/2, भवन क्र-38-MOGRA (LIG) कुल क्षे. 72.00 वर्गमीटर है।
2	स्व. श्री बच्चा उपाध्याय /पिता-स्व. शिवपूजन उपाध्याय पता- मैत्रीकुंज रिसाली भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	(1)चन्द्रवती देवी/पति-स्व. बच्चा उपाध्याय (2) अमृत राज उपाध्याय/पिता-स्व. बच्चा उपाध्याय (3) अनामिका सुमन उपाध्याय/पिता-राजन उपाध्याय (4) श्रेया उपाध्याय/पति-राजन उपाध्याय पालक वली माता श्रीमती अनामिका सुमन उपाध्याय पता-मैत्रीकुंज रिसाली तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	वारिसाना हकत्याग	रिसाली, मैत्रीकुंज रिसाली ख. नं. 95/24 कुल रकबा 0.020 हेक्टेयर है।
3	स्व. कन्हैया लाल महेंद्र /पिता-बेदीलाल महेंद्र पता-पलास टावर के पास, पंचकुटी मैत्रीकुंज रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	(1) श्रीमती धनिष्ठी महेंद्र /पति-स्व. कन्हैया लाल महेंद्र (2) शीतल कुमार महेंद्र/पिता-स्व. कन्हैया लाल महेंद्र (3) हरीश कुमार महेंद्र पता- पलास टावर के पास, पंचकुटी मैत्रीकुंज रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	वारिसाना हकत्याग	पलास टावर के पास, पंचकुटी मैत्रीकुंज रिसाली, प.ह.नं. 22 ख. नं. 74/4, कुल रकबा 0.020 हेक्टेयर है।
4	मेसर्स आकृति इन्फास्ट्रक्चर्स भिलाई पार्टनर- शिव कुमार साहू/पिता-स्व. महाबीर साहू पता-08/53, राधिका नगर सुपेला भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	(1)पूनम कश्यप/पिता-श्री अवध राम (2) शिखा /पिता-अवध राम दोनों निवासी- क्वां नं. 166/सी, रूआबांधा सेक्टर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	बिक्रीनामा	रिसाली प.ह.न. 22 रिसाली एम. एस आकृति इन्फ्रास्ट्राक्चर्स ख.नं. 295/1 कुल रकबा 1523 वर्गफीट, फ्लैट नं. 506 पंचम तल प्रगति नगर रिसाली ।

उक्त संबंध में अंतरण के पूर्व इश्तहार जारी किया जाता है, जिसमें संबंधिती द्वारा प्रकाशन एवं नामांतरण शुल्क जमा किया गया है। अतः समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत।

सहा. राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम, रिसाली

खिड़की पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटकी मिली महिला की लाश

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। दर्री स्थित पुष्प पल्लव कॉलोनी में एक कामकाजी महिला मंजू राव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर की खिड़की से लटका मिला। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, मंजू राव का शव चुनरी के सहारे लटका हुआ था। उनके पति सुनील राव ने बताया कि रात को खाने के बाद सभी सो गए थे। बाद में उन्हें पत्नी के आत्महत्या करने की जानकारी मिली। जिसके बाद उन्होंने परिजनों और पड़ोसियों को सूचित किया। तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पति ने कहा कि उनके बीच सब ठीक था कोई विवाद नहीं था। वहीं मायके वालों ने भी कहा कि शादी के बाद से सब ठीक था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। पति ने कहा कोई विवाद नहीं सुनील राव ने अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह के विवाद या अन्य घटना से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि मंजू दुकान में काम करने जाती थीं। काम से लौटने के बाद सभी ने एक साथ खाना खाया। सुनील टीवी देख रहे थे, जबकि मंजू बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद जब सुनील ने कमरे में जाकर देखा, तो यह घटना सामने आई। मायके वालों ने कहा-शादी के बाद कोई समस्या नहीं थी मंजू द्वारा उठाए गए इस कदम की जानकारी रात में ही खरसिया स्थित उनके परिजनों को मिल गई थी, जिसके बाद वे कोरबा पहुंचे। मंजू की मां बिसुन भट्ट ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 2007 में हुई थी और तब से कोई समस्या सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि मंजू ने कभी किसी परेशानी के बारे में नहीं बताया, यहां तक कि रक्षाबंधन पर भी जब वह बच्चों के साथ खरसिया आई थीं।

जांच में जुटी पुलिस

परिजन इस घटना के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार के संदेह का कोई कारण नहीं मिला था। मृतिका मंजू के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है और एक छोटा बच्चा है। दर्री पुलिस इस मामले में मर्ज कायम कर जांच में जुट गई है।

नाम परिवर्तन

मैं पुष्प लता यादव पुत्री बी.आर. यादव निवासी मकान नं. 153/7 कृष्णा टॉकीज रोड, एच.डी.एफसी. बैंक के पास, आशीष नगर पश्चिम, पोस्ट ऑफिस भिलाई छ.ग. जिला दुर्ग छ.ग. -490006 है। विवाह के पूर्व मेरा नाम पुष्प लता यादव पुत्री बी.आर. यादव था जिसे अब बदल लिया है। विवाह के बाद मेरा नाम पुष्पलता चंद्रप्रकाश यादव पत्नी चंद्रप्रकाश बाबूनंदन यादव हो गया है। अत: सभी सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पलता चंद्रप्रकाश यादव पत्नी चंद्रप्रकाश बाबूनंदन यादव दर्ज किया जावें।

शपथकर्ता
पुष्पलता चंद्रप्रकाश यादव

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

छत्तीसगढ़ शासन सत्यमेव जयते

बस्तर

अब समृद्धि की ओर...

औद्योगिक निवेश और आर्थिक प्रगति का नया दौर

- नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से बस्तर में निवेश के खुले द्वार
- छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के केंद्र में बस्तर
- पर्यटन और छोटे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन
- औद्योगिक माहौल को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई नवाचार
- उद्यमियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, वर्ष में केवल एक बार परीक्षण
- निवेशकों को 'इंसेंटिव कैलकुलेटर' से लाभ की सटीक जानकारी
- उद्योग स्थापना के लिए नक्सल पीड़ित परिवारों को विशेष अनुदान और अतिरिक्त प्रोत्साहन
- पर्यटन, कृषि-बागवानी, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों में निवेश पर विशेष अनुदान और छह वर्षों तक वित्तीय सहायता
- स्थानीय उद्यमियों को उद्योग स्थापना और रोजगार सृजन में प्राथमिकता
- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान
- आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 40% सैलरी सब्सिडी का प्रावधान

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

RO- 45320/2

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950